जितना सोचो उतना सीमित हो जाते हो। बड़ा सोचो, बड़ा पाओ।

इंदौर, जबलपुर, भोपाल, कटनी, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, रायपुर,नरसिंहपुर, सिवनी से एक साथ प्रकाशित

yashbharat.co.in

नये जमाने के साथ..

यश भारत

● वर्ष-01 अंक-127 ● इंदौर ● गुरुवार, 24 सितम्बर , 2026 ● मूल्य- 2 रुपए ● पृष्ठ-8 ● भाद्रपद शुक्ल 13 ● विक्रम संवत् 2083

पांच दिन बैंकिंग सेवाओं पर असर की आशंका, 23 से 25 सितंबर में निपटा लें जरूरी काम

भोपाल, यशभारत। बैंक से जुड़े जरूरी काम हैं तो उन्हें 23 से 25 सितंबर के बीच निपटाना सुविधाजनक रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (FBU) ने 28, 29 और 30 सितंबर 2026 को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का ऐलान किया है। इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण शाखाओं से जुड़ी सेवाओं पर लगातार पांच दिनों तक असर पड़ने की संभावना है।हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं में नकद जमा और निकासी, चेक से जुड़े काम, दस्तावेज जमा करने तथा कर्मचारियों की सहायता से होने वाली अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए जिन ग्राहकों को शाखा जाकर जरूरी काम करना है, वे 23 से 25 सितंबर के बीच इसे पूरा कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहने की उम्मीद है।

जहरीली शराब कांड के 30 हजार के इनामी का शॉर्ट एनकाउंटर

फायरिंग के बाद सागर पुलिस की जवाबी कार्रवाई, पैर में लगी गोली; साथी आशीष साहू भी घायल

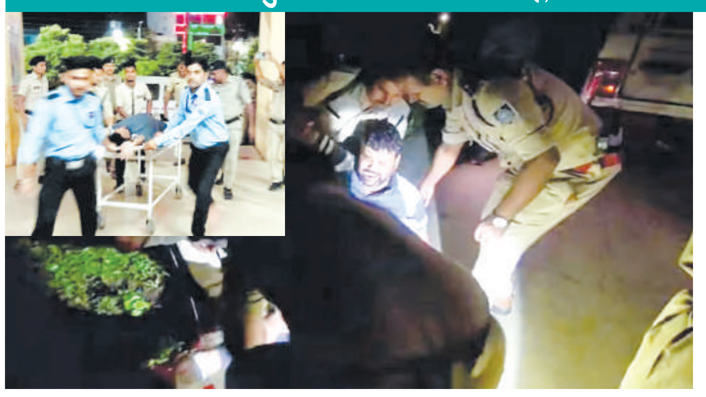

सागर, यशभारत। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सागर में पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस ने बुधवार को मामले के 30 हजार रुपए के इनामी आरोपी मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर और उसके साथी आशीष साहू का शॉर्ट एनकाउंटर किया। मालथौन थाना क्षेत्र के नोनिया-सेसई रोड पर पुलिस और आरोपियों का आमना-सामना हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मनीष लोधी के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी आशीष साहू भी घायल हो गया। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से दो देसी कट्टे, पांच राउंड के खोखे और एक बेसबॉल का डंडा बरामद किया है।

जहरीली शराब कांड सामने आने के बाद से ही सागर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार मनीष लोधी इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस टीमें उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थीं। इसी दौरान बुधवार को पुलिस को उसके मालथौन क्षेत्र में होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नोनिया-सेसई रोड पर घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान आरोपी पुलिस टीम के सामने आ गया और उसने बचने के लिए कथित तौर पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान मनीष के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। उसके साथ मौजूद आशीष साहू भी घायल हुआ। पुलिस ने दोनों को तत्काल कब्जे में लेकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने घटनास्थल से दो देसी कट्टे और पांच राउंड के खोखे बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपियों के पास से बेसबॉल का डंडा भी मिला है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के पास हथियार कहां से पहुंचे और घटना के समय उनके साथ और कौन लोग मौजूद थे।

प्रमुख आरोपी

पुलिस के अनुसार मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर बंडा और विनायका थाना क्षेत्र में सामने आए जहरीली शराब प्रकरण का प्रमुख आरोपी है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतों के बाद इस मामले ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया था। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने अवैध शराब के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज की। इसी कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों और आरोपियों को चिह्नित किया गया। मनीष लोधी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही थी।

भाजपा ने चुनावी राज्यों में बिछाई संगठन की नई बिसातः म प्र में बिप्लब कुमार

स्मृति को छत्तीसगढ़-हरियाणा,राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड और हरीश द्विवेदी को बिहार-कर्नाटक की जिम्मेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी और सह-प्रभारियों की घोषणा कर दी। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से जारी सूची में कई वरिष्ठ नेताओं को एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे अहम बदलाव उत्तर प्रदेश में किया गया है, जहां विनोद तावड़े को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ चार सह-प्रभारियों की टीम भी तैनात की गई है। यह नियुक्तियां ऐसे समय हुई हैं, जब भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राज्यों में संगठनात्मक तैयारियां तेज कर रही है।

नई सूची में स्मृति ईरानी, राम माधव, हरीश द्विवेदी, सतीश पूनिया और सुनील बंसल को दो-दो राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा, हरीश द्विवेदी को बिहार और कर्नाटक, सतीश पूनिया को जम्मू-कश्मीर और पंजाब, राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड तथा सुनील बंसल को तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। अनिल एंटनी को नगालैंड का प्रभारी और गोवा का सह-प्रभारी बनाया गया है।राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड में अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज तथा तमिलनाडु में निर्मल कुमार सुराणा और डीके अरुणा सह-प्रभारी होंगे। हरीश द्विवेदी को बिहार और कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। बिहार में संगीता यादव और रोहन गुप्ता तथा कर्नाटक में डॉ. के. वेंकटेश्वरलू सह-प्रभारी होंगे। वहीं सतीश पूनिया जम्मू-कश्मीर और पंजाब का संगठन देखेंगे। पंजाब में वीरेंद्र सचदेवा और अलका गुर्जर को सह-प्रभारी बनाया गया है। सुनील बंसल तेलंगाना के साथ पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी बिप्लब कुमार देब को दी गई है। रेखा वर्मा सह-प्रभारी होंगी। महाराष्ट्र में बैजयंत जय पांडा प्रभारी और अमित मालवीय, सदानंद शेट तानावडे तथा कमलजीत सहरावत सह-प्रभारी होंगे। राजस्थान में संजय भाटिया के साथ कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को जिम्मेदारी मिली है।

पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट छिंदवाड़ा एसपी पर भी हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर, यशभारत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने न्यायालय के आदेशों की कथित अवहेलना से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए पन्ना कलेक्टर उषा परमार और छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। दोनों अधिकारियों को संबंधित मामलों में आदेशों का पालन नहीं करने और अदालत के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।पन्ना कलेक्टर से जुड़ा मामला कलेक्ट्रेट की पूर्व कर्मचारी जाविन आरी रिजवी की नियमितीकरण संबंधी याचिका से संबंधित है। रिजवी सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 13 अगस्त 2025 को अदालत ने उनके अभ्यावेदन पर 90 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्धारित समयसीमा में आदेश का पालन नहीं होने पर उन्होंने अवमानना याचिका दायर की।

आजमगढ़ में खूनी पूजा का खौफनाक अंत

पत्नी-पुजारियों को गोलियों से भूना, बच्चों को बनाया बंधक

एनकाउंटर में आरोपी ढेर

अरविंद सिंह
मृतक हत्यारा

आजमगढ़, यशभारत। आजमगढ़ जिले के शंभुपुर गांव में मंगलवार शाम हुई सनसनीखेज वारदात के बाद करीब आठ घंटे तक चले गतिरोध का अंत पुलिस मुठभेड़ में हुआ। पत्नी और दो पुजारियों की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी अरविंद सिंह ने अपने तीन बच्चों को घर के भीतर बंधक बना लिया था। पुलिस के मुताबिक, बच्चों को बचाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब अरविंद सिंह के घर में पूजा-पाठ चल रहा था। यह पूजा उसकी पत्नी बबीता ने अपने पति के भाई की मौत के सिलसिले में आयोजित कराई थी। बताया गया है कि अरविंद पहले से ही पूजा-पाठ को लेकर नाराज था। घर लौटने के बाद उसने पूजा में मौजूद पुजारियों को लेकर आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और उसने पत्नी बबीता तथा पूजा कराने आए दो पुजारियों पर गोली चला दी। इनमें महेंद्र पाठक की पहचान पुजारी के रूप में हुई है। घटना के दौरान दो अन्य पुजारी मौके से भागने में सफल रहे। तीनों की हत्या के बाद अरविंद ने अपने तीन बच्चों को घर के भीतर बंद कर लिया और खुद भी अंदर रहकर पुलिस को चुनौती देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेर लिया और आरोपी से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने तथा आत्मसमर्पण करने की लगातार अपील की। आजमगढ़ एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के मुताबिक, आरोपी बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसी दौरान उसने कमरे के भीतर बच्चों पर भी गोली चलाई, जिसमें उसके 10 वर्षीय बेटे को गोली लग गई। पुलिस के मुताबिक, बच्चों की ओर से खतरा सामने आने के बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई की। गोली चलने की आवाज सुनाई देने पर पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें अरविंद को गोली लगी। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर, गोली लगने से घायल 10 वर्षीय बेटे को भी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

चुनाव आयोग में दरार के दावे से सियासी तूफान, ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष हमलावर

संधू-जोशी ने 10 माह में 14 बार दर्ज कराई आपत्ति, SIR और वोटर डेटा पर उठाए सवाल आयोग ने कहा- सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए

नई दिल्ली, एजेंसी। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रक्रिया को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट ने बहस को और तेज कर दिया है। एक अंग्रेजी दैनिक की जांच के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों और जारी आदेशों पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों आयुक्तों ने कुछ फैसलों को अपनी जानकारी या सहमति के बिना लिए जाने का दावा किया और कुछ कदमों को 'अनधिकृत' तथा 'अवैध' बताया।रिपोर्ट के मुताबिक, आपत्तियों का संबंध नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाल करने, स्ढ्ढक्र से जुड़े मामलों में अपील तथा मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस और आईटी सिस्टम के नियंत्रण से था। चार आपत्तियां एक ही दिन दर्ज किए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं।

फॉर्म-6 में बदलाव पर भी सवाल

रिपोर्ट के अनुसार, नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में SIR से जुड़े सवाल जोड़े जाने पर भी आपत्ति दर्ज की गई थी। इसमें नए मतदाता या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का पिछली स्ढ्ढक्र की मतदाता सूची में नाम होने से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। संधू और जोशी ने इस बदलाव की प्रक्रिया और अधिकार को लेकर सवाल उठाए थे। मतदाता डेटा के आईटी प्रबंधन को लेकर भी दोनों आयुक्तों ने चिंता जताई। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने चुनावी रोल के डिजिटल सिस्टम और सॉफ्टवेयर तक पहुंच को दिल्ली में केंद्रीकृत किए जाने पर सवाल उठाए तथा इस संबंध में कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखे। रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और स्ढ्ढक्रप्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। कुछ विपक्षी नेताओं ने कुमार को हटाने की मांग भी उठाई है। इन मांगों को राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में कल से दौड़ेंगी सुगम परिवहन सेवा की बसें, 351 बसों को सीएम दिखाएंगे हरी झंडी

भोपाल, यशभारत। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ 25 सितंबर से होगा। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शुरुआती चरण में प्रदेश के सात प्रमुख शहरों में बस सेवा शुरू होगी और इसके बाद करीब 1500 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। पहले चरण में 351 बसों में 120 इंटरसिटी और 231 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं। इंटरसिटी बसें दो या उससे अधिक शहरों के बीच आवागमन की सुविधा देंगी, जबकि इंट्रासिटी बसों का संचालन शहरों के भीतर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस सेवा का उद्देश्य शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक

परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।पहले चरण में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड में बसें संचालित होंगी। इंदौर में 145 बसें, भोपाल में 106 और जबलपुर में 67 बसें चलेंगी। इंदौर में 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी, भोपाल में 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी तथा जबलपुर में 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं। रीवा में 18, देवास में 10, कटनी में 3 और भिंड में 2 इंटरसिटी बसें शुरू की जाएंगी।सरकार ने वर्ष 2031 तक 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत प्रदेश में करीब 15 हजार आधुनिक सार्वजनिक बसें संचालित करने और 180 से अधिक बस स्टैंड, टर्मिनल तथा डिपो का कायाकल्प करने की योजना है। सरकार के अनुसार इससे प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को परिवहन सुविधा मिल सकेगी।यात्री सुरक्षा के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं।

मीराबाई ने रचा इतिहास, एशियाड में भारत को 28 साल बाद दिलाया भारोत्तोलन पदक

49 किग्रा वर्ग में 198 किग्रा वजन उठाकर जीता रजत, एशियाई खेलों में पहली बार पदक से बढ़ाया देश का गौरव

आइची-नागोया, एजेंसी। भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए महिलाओं की 49 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। मीराबाई ने कुल 198 किग्रा वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। उनके इस पदक के साथ ही एशियाई खेलों में भारोत्तोलन में भारत का 28 साल से चला आ रहा पदक का इंतजार खत्म हो गया। मीराबाई ने स्नैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 83 किग्रा से शुरुआत की। दूसरे प्रयास में उन्होंने 85 किग्रा और तीसरे प्रयास में 87 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया। स्नैच के बाद वह पदक की दौड़ में मजबूती से बनी हुई थीं। क्लीन एंड जर्क में भी मीराबाई ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले प्रयास में 107 किग्रा और दूसरे प्रयास में 111 किग्रा वजन उठाया। इसके बाद उन्हें तीसरे प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस तरह उनका कुल स्कोर 87 किग्रा स्नैच और 111 किग्रा क्लीन एंड जर्क मिलाकर 198 किग्रा रहा।

उत्तर कोरिया की रि सोंग गुम को स्वर्ण

स्पर्धा में उत्तर कोरिया की रि सोंग गुम ने 215 किग्रा के कुल वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 94 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 121 किग्रा वजन उठाया। इंडोनेशिया की विजायाना लुलुक डियाना त्रि ने 191 किग्रा के कुल स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

1998 के बाद भारत को मिला पदक

मीराबाई के रजत पदक ने एशियाई खेलों में भारोत्तोलन के क्षेत्र में भारत का लंबा इंतजार समाप्त कर दिया। भारत ने इससे पहले 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। उसके बाद भारतीय भारोत्तोलकों को एशियाई खेलों में पदक नहीं मिल सका था। मीराबाई ने 28 साल बाद इस सिलसिले को तोड़ दिया।

भारत की पदक तालिका में भी इजाफा

मीराबाई के रजत पदक से एशियाई खेलों में भारोत्तोलन में भारत के कुल पदकों की संख्या 15 हो गई है। इनमें छह रजत और नौ कांस्य पदक शामिल हैं। हालांकि, भारत अब तक एशियाई खेलों में भारोत्तोलन का स्वर्ण पदक नहीं जीत सका है। एशियाड के चौथे दिन भारत के पदकों की संख्या में अन्य स्पर्धाओं से भी इजाफा हुआ। शॉटगन शूटिंग के महिला स्कीट टीम इवेंट में रायजा ढिल्लों, परिनाज धालीवाल और माहेश्वरी चौहान ने कांस्य पदक जीता। पुरुष स्कीट टीम में अनंतजीत सिंह नारुका, मैराज अहमद खान और भवतेघ सिंह गिल ने शूट-ऑफ में कजाकिस्तान को हराकर कांस्य हासिल किया। सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा ने भी भारत को पदक दिलाया। वहीं, निशानेबाजी की महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर 181.1 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। टीम स्पर्धा में भी भारतीय टीम मामूली अंतर से पदक से चूक गई।

मंत्रियों की 'क्लास आज से रिव्यू, तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

नई दिल्ली, यशभारत। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए बुधवार से दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया। 'विकसित भारत@2047' की थीम पर आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ सरकार की प्राथमिकताओं, योजनाओं की प्रगति और जनता से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे। शिविर 24 सितंबर तक चलेगा। पहले दिन मंत्रियों को अपने विभाग और क्षेत्र से जुड़े कामकाज पर प्रेजेंटेशन देना है। दूसरे दिन इन प्रस्तुतियों और काम की समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रियों के प्रदर्शन को 'एक्सीलेंट, गुड, एवरेज और पुअर' जैसी श्रेणियों में आंका जा सकता है। तैयार रिपोर्ट कार्ड को भविष्य में कैबिनेट फेरबदल के दौरान भी आधार बनाए जाने की चर्चा है।

Gen z और रोजगार पर खास फोकस - चिंतन शिविर में युवाओं, खासकर त्नद्गठ्ठ के साथ संवाद, रोजगार और मौजूदा मुद्दों को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा होगी। मंत्रियों से पूछा जाएगा कि उन्होंने युवाओं के साथ संवाद के लिए अब तक क्या कदम उठाए, उनके क्षेत्र में युवाओं के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या योजना बनाई गई है। UGC से जुड़े मुद्दे भी एजेंडे में बताए गए हैं। इसके अलावा महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित विधायी कदमों पर भी चर्चा और मंत्रियों से सुझाव लिए जाने की बात सामने आई है।

एआई से बदला युद्ध का चेहरा, ड्रोन बने नए हथियार

मदन गर्ग

जबलपुर। कभी शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में वीडियोग्राफी तथा फूल बरसाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन आज आधुनिक युद्ध के महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने ड्रोन की सैन्य उपयोगिता को व्यापक स्तर पर सामने रखा है। निगरानी से लेकर सटीक हमलों और काउंटर-ड्रोन अभियानों तक इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है।

आधुनिक युद्ध में छोटे एफपीवी (First Person View) ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन, मानवरहित हवाई वाहन (UAV) और ड्रोन स्वार्म महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एफपीवी ड्रोन को ऑपरेटर कैमरे के माध्यम से नियंत्रित करता है और युद्धक्षेत्र में निगरानी तथा लक्षित हमलों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लोइटरिंग म्यूनिशन लक्ष्य क्षेत्र में कुछ समय तक मंडराने के बाद लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम होते हैं।

ड्रोन तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। इससे नेविगेशन, वस्तु पहचान और लक्ष्य की निगरानी जैसे कार्य अधिक स्वचालित हो सकते हैं। वहीं ड्रोन स्वार्म में बड़ी संख्या में ड्रोन नेटवर्क के माध्यम से समन्वित तरीके से काम करते हैं। इससे एक साथ कई दिशाओं से कार्रवाई करने की क्षमता विकसित होती है।

रूस-यूक्रेन युद्ध को ड्रोन युद्ध के बड़े प्रयोगक्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। दोनों पक्षों ने निगरानी और हमलों के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। सितंबर 2026 में यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ एक बड़े अभियान में एक हजार से अधिक ड्रोन इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट सामने आई। इससे युद्ध में ड्रोन की बढ़ती भूमिका का अंदाजा लगाया जा सकता है।

भारत ने भी ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक पर अपना ध्यान बढ़ाया है। भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ -9B ड्रोन की खरीद का अनुबंध किया है। इनमें 16 SeaGuardian और 15 SkyGuardian शामिल हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी की निगरानी और समुद्री क्षेत्र की निगरानी जैसे अभियानों में किया जा सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक का महत्व सामने आया। भारत की एकीकृत वायु-रक्षा और काउंटर-यूएएस प्रणालियों ने ड्रोन खतरों से निपटने में भूमिका निभाई। इसके साथ ही स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणालियों के विकास पर जोर बढ़ा है। भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी ड्रोन क्षमता बढ़ाने में जुटे हैं। पाकिस्तान ने चीन और तुर्किये के साथ सहयोग के जरिए अपनी मानवरहित हवाई क्षमता विकसित की है। बांग्लादेश ने चीन के साथ स्थानीय स्तर पर ड्रोन निर्माण और असेंबली क्षमता विकसित करने के लिए समझौता किया है।

ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ काउंटर-ड्रोन तकनीक भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। रेडियो-फ्रीक्वेंसी जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, माइक्रोवेव और डायरेक्टेड-एनर्जी जैसी तकनीकों पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर, ड्रोन ने युद्ध की रणनीति और तकनीक दोनों को बदलना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में एआई, स्वार्म और स्वायत्त प्रणालियां युद्धक्षेत्र की तस्वीर को और बदल सकती हैं। भारत के लिए चुनौती अत्याधुनिक ड्रोन बनाने के साथ-साथ मजबूत ड्रोन-रोधी सुरक्षा तंत्र विकसित करने की भी है।

सात प्रमुख विसर्जन स्थलों का आयुक्त ने किया निरीक्षण, 1399 प्रतिमाओं का विधि-विधान से कराया गया विसर्जन

गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए निगम ने संभाली कमान

भोपाल, यश भारत।

गणेश प्रतिमाओं के ससम्मान और सुरक्षित विसर्जन के लिए नगर निगम ने शहरभर में व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। डोल ग्यारस पर छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 25 अस्थायी एकत्रीकरण केंद्र और चार विसर्जन घाट बनाए गए। समाचार लिखे जाने तक इन केंद्रों और घाटों पर कुल 1399 गणेश प्रतिमाएं प्राप्त कर विधि-विधान से विसर्जित कराई जा चुकी थीं।

विसर्जन व्यवस्था का जायजा लेने निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने मंगलवार सुबह शहर के सात प्रमुख विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रेमपुरा, रानी कमलापति, खटलापुरा, शाहपुरा, बैरागढ़, मालीखेड़ी और हथाईखेड़ा स्थित घाटों व कुंडों पर व्यवस्थाएं देखीं। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विसर्जन के दौरान प्रकाश, पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था में किसी तरह की कमी न रहे। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए क्रेन सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने तथा विसर्जन के बाद प्रतिमाओं के अवशेष तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए।

सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी

विसर्जन के दौरान सुरक्षा को लेकर घाटों पर बैरिकेडिंग, गोताखोर, नाव और आवश्यक उपकरणों से लैस अग्निशमन दल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रमुख विसर्जन स्थलों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से व्यवस्थाओं के संचालन के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र और सूचना पट्टों की व्यवस्था भी रखने को कहा गया।

खटलापुरा घाट पर सबसे ज्यादा 564 प्रतिमाएं

जोन स्तर पर बनाए गए प्रतिमा एकत्रीकरण केंद्रों और विसर्जन घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने छोटी गणेश प्रतिमाएं निगम को सौंपीं। बैरागढ़ अग्निशमन केंद्र पर 63, शाहपुरा विसर्जन घाट पर 100 और खटलापुरा घाट पर सबसे अधिक 564 प्रतिमाएं प्राप्त हुईं। पांच नंबर तालाब, नेहरू नगर और पीएंडटी चौराहा केंद्रों पर 88 प्रतिमाएं पहुंचीं।

मीनाल रेसीडेंसी केंद्र पर 56, कालीजी मंदिर पर 35, लालघाटी क्षेत्र में 20 तथा नादरा बस स्टैंड और मंगलवारा क्षेत्र में 13 प्रतिमाएं प्राप्त हुईं। वहीं नीलबड़, प्रेमपुरा और रानी कमलापति क्षेत्र में कुल 398 प्रतिमाएं पहुंचीं। अन्य जोन के एकत्रीकरण केंद्रों पर भी प्रतिमाएं प्राप्त कर उनका विधि-विधान से विसर्जन कराया गया।

निगम आयुक्त ने डोल ग्यारस पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए अस्थायी एकत्रीकरण एवं विसर्जन स्थलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने छोटी प्रतिमाओं को कुंडों और निर्धारित पात्रों में विधि-विधान से विसर्जित कराने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अक्षय कुमार तेम्रवाल, तन्मय वशिष्ठ शर्मा, वरुण अवस्थी, अमन मिश्रा, अभिषेक सिंह, वरुण बड़ेरिया, उपायुक्त भुवन गुप्ता व चंचलेश गिरहारे सहित मुख्य अभियंता संतोष गुप्ता, अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग, आर.आर. जरोलिया और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

डोल ग्यारस पर राधाकृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना

भोपाल, यश भारत। महापौर मालती राय ने डोल ग्यारस के अवसर पर बरखेड़ी स्थित राधाकृष्ण मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान राधाकृष्ण के दर्शन कर धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जोगी समाज की ओर से महापौर का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में हेमंत जोगी, साधना यादव, देवेंद्र जोगी सहित समाज के पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे।

सीबीएसई पश्चिम क्षेत्र टेनिस प्रतियोगिता का समापन, विजेता खिलाड़ियों को मिले पुरस्कार

भोपाल, यश भारत।

खेल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रभावी माध्यम हैं। यह बात नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने आईईएस पब्लिक स्कूल में आयोजित सीबीएसई पश्चिम क्षेत्र टेनिस प्रतियोगिता के समापन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश और गुजरात के बालक-बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन अवसर पर विभिन्न वर्गों के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने निगम अध्यक्ष का भी सम्मान किया।

बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेज

भोपाल, यश भारत । मुंबई-अहमदाबाद उच्च गति रेल परियोजना के तहत बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहले खंड का निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है और 2027 में इस पर सेवा शुरू करने की तैयारी है। ट्रेन के ढांचे, बोगी, प्रणोदन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पहिए और पेंटोग्राफ पर काम जारी है। ट्रेन के ढांचे की मजबूती की जांच के लिए परीक्षण भी किया जा रहा है। सेवा शुरू होने से पहले व्यापक परीक्षण किए जाएंगे। बीकेसी-ठाणे समुद्र के नीचे बनने वाली सुरंग का काम भी आगे बढ़ रहा है। शाफ्ट और दोनों टनल बोरिंग मशीनों की स्थापना पूरी हो चुकी है। कॉरिडोर में सुरंग, स्टेशन और पुल निर्माण के कार्य भी जारी हैं।

1120 दीपक जलाकर संतजी के संदेश को दोहराया

एलवीएस ने मनाया अवतरण दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम

हिरदाराम नगर, यशभरत।

लक्ष्मीदेवी विक्योमल शर्राफ एज्यूकेशनल सोसायटी गांधीनगर के विद्यालयों में संत हिरदाराम साहिबजी के अवतरण दिवस पर कुटिया पर 1120 दीपक प्रज्ज्वलित किए गए विद्यालय में विद्यार्थियों ने संत जी के जीवन और विचारों पर आधारित भजन, नाटक, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संस्था के रमेश हिंगोरानी ने कहा कि संत हिरदाराम साहिब जी का जीवन सत्य, प्रेम, सेवा और मानवता का प्रतीक है, जो समाज को हमेशा सकारात्मक दिशा दिखाता रहेगा। अंत में, सभी छात्रों और शिक्षकों ने रामधुनी का गायन कर संत जी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और सम्मान प्रकट किया।गणमान्य नागरिक, शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे।

सेवा, सुमिरन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शांति के दीप जलाए

संत हिरदाराम जी साहिब के 120वें अवतरण दिवस पर संतनगर सहित विभिन्न शहरों में दीप प्रज्ज्वलित कर संतजी सेवा, सुमिरन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शांति के संदेश को दोहराया गया। संतनगर में शाम 7 बजे प्रत्येक घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान पर पाँच-पाँच दीप जलाए गए। संतजी के समाधि स्थल पर 1,120 दीपों की ज्योति प्रज्ज्वलित की गई। यह दीप केवल प्रकाश के प्रतीक नहीं थे, बल्कि संत जी के सेवा, सुमिरन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शांति के संदेश को आने वाली पीढ़ियों तक 1,000 वर्षों तक पहुँचाने के अटूट संकल्प का प्रतीक बने। इस अवसर पर जीव सेवा संस्थान सचिव महेश दयारामनी व गणमान्य लोग शामिल हुए

मनुआभान टेकरी प्लांट से आज जलप्रदाय रहेगा प्रभावित

भोपाल, यश भारत। मनुआभान टेकरी जलशोधन संयंत्र में आवश्यक संधारण और राष्ट्रीय राजमार्ग के इंटर कनेक्शन कार्य के चलते बुधवार, 23 सितंबर को सुबह 5 बजे से रात 11.59 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। इसके कारण प्लांट से जुड़े कई क्षेत्रों में जलप्रदाय प्रभावित रहेगा। ब्लूमून कॉलोनी, नवाब कॉलोनी, प्रेमनगर, सुंदरनगर, रासलाखेड़ी, मालीखेड़ी, भानपुर रोड, करोंद, देवकी नगर, कमल नगर, पंचवटी कॉलोनी, छोला मंदिर, सत्यज्ञान नगर, शंकर नगर, टिंबर मार्केट, नगर निगम कॉलोनी सहित संबंधित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार

छात्र संघ पदाधिकारियों को दिलाई शपथ

भोपाल, यश भारत।

महापौर मालती राय ने शिवाजी नगर स्थित शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्र संघ की नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। महापौर ने छात्राओं को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने और विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पार्षद शिखा गोहल, प्राचार्य, शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहीं।

52 स्थानों से लिए पानी के नमूने, छह लीकेज सुधारे

भोपाल, यश भारत। शहर में पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नगर निगम ने मंगलवार को 52 स्थानों से पानी के नमूने लिए। इसके साथ ही छह स्थानों पर पाइपलाइन के लीकेज सुधारे गए और जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों का निराकरण किया गया। निगम के अनुसार अब तक 30477 पानी के नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें 13983 नमूने झुग्गी बस्ती क्षेत्रों से हैं। इनकी जांच निगम की आठ परीक्षणशालाओं में की जा रही है। जलकार्य अमले ने इब्राहिमगंज, वाजपेयी नगर, अहीर मोहल्ला, सोनागिरी और दानिशकुंज सहित अन्य क्षेत्रों में लीकेज सुधारे।

90 आवारा श्वान पकड़े, नसबंदी के लिए भेजे

भोपाल, यश भारत। नगर निगम ने आवारा श्वानों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 90 श्वान पकड़े। इन्हें नसबंदी केंद्रों में भेजा गया। नसबंदी के बाद 87 श्वानों को उसी स्थान पर वापस छोड़ा गया। निगम के डॉग स्क्वाड ने 30 श्वानों को कजलीखेड़ा, 28 को आदमपुर और 29 को अरवलिया स्थित एबीसी केंद्र भेजा। निगम के अनुसार आवारा श्वानों को पकड़ने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

21 पशु कांजी हाउस भेजे, सात घायल पशु अस्पताल पहुंचे

भोपाल, यश भारत।

नगर निगम ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर खुले में घूम रहे पशुओं के खिलाफ अभियान चलाते हुए मंगलवार को 21 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा। बीमार और घायल सात पशुओं को आसरा पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। निगम की हांका पार्टी ने 15 पशुओं को सड़कों से हटाया, जबकि 18 पशुओं को खजूरीकलां कांजी हाउस से रामकृष्ण गौशाला भेजा गया। मालीखेड़ी, संत हिरदाराम नगर, प्रेमपुरा, खटलापुरा, शाहपुरा, हथाईखेड़ा, रानी कमलापति घाट, कमला पार्क, आनंद नगर, करोंद, भानपुर, बैरागढ़, लालघाटी और कोलार रोड सहित कई क्षेत्रों में अभियान चलाया गया।

बीना स्टेशन पर काम से बदलेगा ट्रेनों का संचालन

भोपाल, यह भारत ।

बीना स्टेशन पर तीसरी रेल लाइन की कनेक्टिविटी से जुड़े प्री-एनआई और एनआई कार्य के चलते अक्टूबर में कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं, जबकि कुछ को बीच के स्टेशनों से चलाया जाएगा। गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस और 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस 1 से 15 अक्टूबर तक परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस संत हिरदाराम नगर, मक्सी और रूठियाई होकर कोटा जाएगी।

दमोह-बीना पैसेंजर 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बीना मालखेड़ी पर समाप्त होगी और बीना-ग्वालियर पैसेंजर इसी स्टेशन से शुरू होगी। रूठियाई-बीना और बीना-रूठियाई मेमू 18 से 29 सितंबर तक महादेवखेड़ी से चलेंगी। वहीं इटारसी-भोपाल और भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस 9 से 15 अक्टूबर तक दमोह तक ही संचालित होंगी।

एसएचआईएम की सलोनी एवं मुस्कान ने फाइनल में जगह बनाई

एसएचआईएम में हुआ नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज का सेंट्रल रीजनल राउंड

हिरदाराम नगर, यशभारत।

संत हिरदाराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसएचआईएम में सेबी के मार्गदर्शन में एनआईएसएम द्वारा 19-20 सितंबर 2026 को नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज के सेंट्रल रीजनल राउंड का आयोजन किया गया। देशभर के 2,000 से अधिक कॉलेजों और 4 लाख विद्यार्थियों में से मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ यूजी और पीजी वर्ग की 60-60 टीमों का चयन इस चरण के लिए हुआ था।

प्रतिस्पर्धा में आईआईएम रायपुर, वीआईटी भोपाल और सिम्बायोसिस इंदौर जैसे प्रमुख संस्थानों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता से भोपाल की यूजी वर्ग की 4 और पीजी वर्ग की 2 टीमें राष्ट्रीय फाइनल के लिए क्वालीफाई हुईं। एसएचआईएम की सलोनी वर्मा एवं मुस्कान साहू ने राष्ट्रीय स्तर के फाइनल में अपनी जगह बनाई।

राष्ट्रीय फाइनल का आयोजन 30 नवंबर 2026 को एनआईएसएम मुंबई में होगा। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर हीरो ज्ञानचंदानी, डायरेक्टर डॉ. आशीष ठाकुर एवं ग्रुप एडवाइजर पी. एस. राठौर ने विजेता छात्राओं को बधाई दी है।

15 दिनों के अंदर खामियां दूर करने का अल्टीमेटम दिया

ब्रिज निर्माण की प्रगति देखने आए लोनिवि मंत्री ने अफसरों और निर्माण कंपनी को लगाई फटकार

हिरदाराम नगर, यशभारत

संत हिरदाराम नगर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज और उसके आसपास की बदहाल सड़कों की जमीनी हकीकत परखने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री राकेश सिंह मंगलवार को अचानक निरीक्षण पर पहुँचे। स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ निर्माण स्थल का जायजा लेते हुए मंत्री ने मौके पर फैली अव्यवस्थाओं पर गहरी नाराजगी जताई। कार्य की धीमी रफ्तार और लापरवाही को देखते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और अगले 15 दिनों के भीतर सभी खामियों को दुरुस्त करने का कड़ा अल्टीमेटम दिया।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर पेनाल्टी के आदेश

स्थल निरीक्षण के दौरान निर्माण क्षेत्र की सड़कें बेहद जर्जर और बड़े-बड़े गड्ढों से भरी पाई गईं। स्ट्रीट लाइटें बंद रहने और सुरक्षा के बुनियादी इंतज़ाम न होने पर रोष जताते हुए मंत्री ने मौके पर ही निर्माण कंपनी पर पेनाल्टी ठोकने के कड़े निर्देश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों को धूल से निजात दिलाने के लिए नियमित पानी के छिड़काव, सिविल अस्पताल के पास की अव्यवस्थाओं को ठीक करने और रात में काम के दौरान पर्याप्त लाइटिंग व सुरक्षा घेरा सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

ग ों की शिकायत के लिए जनता से मदद की अपील

जनसुविधा को सर्वोपरि बताते हुए मंत्री राकेश सिंह ने एक नई पहल का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी की किसी भी सड़क पर गड्ढा दिखने पर आम नागरिक उसकी फोटो खींचकर साझा कर सकते हैं, ताकि विभाग उस पर तुरंत कार्रवाई कर सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इंजीनियरों की कार्यशैली में सुधार लाया जा रहा है और जनता को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण सड़कें उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

तय समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

यद्यपि इस फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को पूरा करने की मूल समय-सीमा अक्टूबर तय की गई है, फिर भी मंत्री ने पूरी प्रशासनिक कसावट के साथ काम में तेज़ी लाने पर बल दिया। विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ पूरे मार्ग का मुआयना करने के बाद उन्होंने अब तक हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों से आगे की कार्ययोजना की जानकारी लेते हुए समय पर काम पूरा करने की हिदायत दी।

चुनाव आयोग के भीतर मतभेद पर उद्धव ठाकरे का हमला

ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग, फैसलों की प्रक्रिया पर उठे सवाल

मुंबई, यशभारत। चुनाव आयोग के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों को लेकर कथित मतभेद सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

जानकारी के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में कई मौकों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की निर्णय प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, दोबारा नाम दर्ज करने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसले शामिल बताए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। ठाकरे गुट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के भीतर ही महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं, तो उसकी कार्यप्रणाली को लेकर स्पष्टीकरण जरूरी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ मामलों में चुनाव आयुक्तों ने संबंधित निर्णयों से पहले पर्याप्त जानकारी साझा नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई। मतदाता सूची से जुड़े तकनीकी काम के केंद्रीकरण और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। एक लिखित आपत्ति में आयोग के एक निर्णय की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर अलग-अलग सभी बिंदुओं को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आयोग का कहना है कि एसआईआर से संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

लातूर में 1972 से भी गंभीर सूखा

फसलें बर्बाद, पानी-चारे का संकट
फडणवीस ने दिया मदद का भरोसा

लातूर, यशभारत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को लातूर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। खेतों में फसलों को हुए नुकसान के साथ पानी और चारे की कमी को देखते हुए उन्होंने हालात को बेहद गंभीर बताया। फडणवीस ने कहा कि कुछ इलाकों में इस बार की स्थिति 1972 के भीषण सूखे से भी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को व्यापक स्तर पर सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि किसानों को नियमों का हवाला देकर राहत से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि, नुकसान का पंचनामा करना कानूनी प्रक्रिया है और इसे पूरा करना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की कोशिश केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वास्तविक नुकसान के आधार पर सहायता पहुंचाई जाएगी। फडणवीस ने प्रशासन को सूखे की स्थिति का विस्तृत आकलन कर आवश्यक उपायों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मराठवाड़ा के कई हिस्सों में पानी और पशुओं के चारे का संकट गहराने के बीच सरकार ने प्रभावित किसानों तक राहत पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है और स्थिति के अनुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय सम्मान मिलते ही बाप्पा की शरण में कार्तिक

लालबाग के राजा के चरणों में अर्पित किया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

मुंबई, यशभारत। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के बाद सबसे पहले लालबाग पहुंच कर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया। 'चंदू चैंपियन' में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के बाद कार्तिक अपने सम्मान को साथ लेकर मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने पुरस्कार बाप्पा के चरणों में अर्पित किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कार्तिक नीले कुर्ते और सफेद पायजामे में लालबाग के राजा के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। पुरस्कार बाप्पा को समर्पित करने के बाद उन्होंने गणपति का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। राष्ट्रीय सम्मान के तुरंत बाद मंदिर पहुंचने के उनके इस अंदाज की प्रशंसकों ने सराहना की।

कार्तिक को यह पुरस्कार 2024 में रिलीज हुई 'चंदू चैंपियन' में पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर की भूमिका के लिए मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। पुरस्कार मिलने के बाद कार्तिक ने अपने ग्वालियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि छोटे शहर से अभिनेता बनने का सपना देखना आसान नहीं था। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय निर्देशक कबीर खान और निर्माता साजिद नाडियाडवाला को भी दिया।

'जब संस्था के भीतर ही आरोप हैं तो भरोसा किस पर करें?'

निर्वाचन आयोग में मतभेद पर सुप्रिया सुले का सवाल

मुंबई, यशभारत। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आयोग के दो अन्य सदस्यों के बीच मतभेद सामने आने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के भीतर से ही आरोप सामने आना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।

दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सुले ने कहा कि यह केवल राजनीतिक विषय नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला है। मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर उठे सवालों पर सभी राजनीतिक दलों को तत्काल बैठक कर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जुड़े सवाल पर सुले ने कहा कि इस मामले में नैतिकता का परिचय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है। सुले ने कहा कि भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है और प्रत्येक नागरिक को समान मताधिकार संविधान ने दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक भी हो सकती है। वहीं, महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति को लेकर सुले ने सरकार से किसानों के पक्ष में ठोस सहायता देने की मांग की।

17 साल पुराने मानहानि मामले में फैसला आज

उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समेत चार आरोपी
2009 की चुनावी सभा से जुड़ा है मामला

मुंबई, यशभारत। दिवंगत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता वसंत डावखरे से जुड़े करीब 17 साल पुराने मानहानि मामले में बुधवार, 23 सितंबर को फैसला सुनाया जाना है। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान कल्याण में आयोजित एक सभा में कथित आपत्तिजनक सीडी दिखाए जाने के मामले में यह मुकदमा दायर किया गया था। मामले में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समेत कुल चार आरोपी हैं। वसंत डावखरे की ओर से दायर इस मामले की सुनवाई के दौरान 20 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए गए थे। आरोपियों की ओर से सभी आरोपों को गलत बताया गया है। फैसले के समय उद्धव ठाकरे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहेंगे, जबकि अन्य आरोपियों के भी प्रत्यक्ष या ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहने की जानकारी सामने आई है। एकनाथ शिंदे बुधवार को विदर्भ के दौरे पर हैं, जहां वे अकोला और वाशिम जिलों में वर्षा की कमी से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में इस मामले के फैसले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी हुई है।

म्हाडा लॉटरी की तारीख बढ़ी 15 अक्टूबर तक मौका

4,462 घरों के लिए 82 हजार से ज्यादा आवेदन
25 नवंबर को निकलेगा ड्रा

मुंबई, यशभारत। म्हाडा के पुणे मंडल की 4,462 घरों की लॉटरी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। इच्छुक आवेदक अब इस तारीख तक पंजीकरण के साथ आवेदन और निर्धारित अनामत राशि जमा कर सकेंगे। लॉटरी का ड्रा 25 नवंबर को निकाला जाएगा। योजना को आवेदकों की ओर से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। 23 सितंबर तक 82,223 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि 44,531 आवेदकों ने अनामत राशि के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है। म्हाडा के अनुसार, केवल अनामत राशि जमा करने वाले आवेदक ही लॉटरी में शामिल होंगे। इस लॉटरी में 15 प्रतिशत सामाजिक आवास योजना के 1,491 घर और 20 प्रतिशत समावेशी आवास योजना के 2,971 घर शामिल हैं। म्हाडा ने अगस्त में विज्ञापन जारी कर 14 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर और ड्रा 13 अक्टूबर को होना था। आवेदन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें सामने आई थीं। इसके अलावा गणेशोत्सव के कारण भी आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हुई। इन परिस्थितियों को देखते हुए म्हाडा ने आवेदन की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई समयसीमा से आवेदकों को आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

बीएमसी पहली बार बॉन्ड से जुटाएगी 9,500 करोड़

मुंबई के बड़े प्रकल्पों को मिलेगा फंड, मार्च 2027 तक पहली बिक्री की तैयारी

मुंबई, यशभारत। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) वर्ष 2027 की शुरुआत में पहली बार नगर निकाय बॉन्ड जारी कर करीब 9,500 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, बॉन्ड की पहली बिक्री मार्च 2027 तक होने की संभावना है। यह राशि एक या अधिक चरणों में जुटाई जा सकती है।

बॉन्ड के जरिए जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल मुंबई की बुनियादी सुविधाओं और बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। इनमें परिवहन, जलापूर्ति, सीवरेज और अन्य शहरी आधारभूत ढांचा परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं। इससे बीएमसी को पारंपरिक बैंक ऋण के अलावा पूंजी बाजार से सीधे धन जुटाने का विकल्प मिलेगा। प्रस्तावित 9,500 करोड़ रुपये की बॉन्ड बिक्री को किसी भारतीय स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित सबसे बड़े बॉन्ड निर्गमों में से एक माना जा रहा है। महाराष्ट्र के कई अन्य नगर निकाय भी विकास कार्यों के लिए बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नगर निकायों को अपने बड़े प्रकल्पों के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बॉन्ड बाजार को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीएमसी की प्रस्तावित पहल से मुंबई की विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की उम्मीद है। हालांकि, बॉन्ड जारी करने की अंतिम समयसीमा और शर्तों को लेकर आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।

सूखे जैसे हालात पर फडणवीस का अलर्ट

मंत्रियों को सर्वे के आदेश, किसानों को राहत की तैयारी

नागपुर, यशभारत। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश के लंबे अंतराल से पैदा हुए सूखे जैसे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में प्राथमिक आकलन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में संभावित नुकसान का जायजा लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू करने के संकेत दिए हैं।

फडणवीस ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में बारिश की स्थिति और फसलों पर पड़े असर की समीक्षा की गई। कई क्षेत्रों में बारिश के लंबे अंतराल के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक सप्ताह में प्राथमिक समीक्षा पूरी की जाएगी। इसके बाद आधिकारिक फसल सर्वेक्षण कराया जाएगा और प्रभावित किसानों को सहायता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया भी जारी है। अब तक तीन सूचियां जारी की जा चुकी हैं और शेष सूचियों का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में पीने के पानी और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर भी सरकार का ध्यान है। संभावित अल नीनो प्रभाव को देखते हुए पहले से तैयारी की जा रही थी। चारे की कमी दूर करने के लिए 'वैरन विकास' कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसानों को शाम के समय अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। इससे पहले शरद पवार ने 18 सितंबर को राज्य में सूखा घोषित कर प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज देने की मांग की थी।

कैग रिपोर्ट के बाद मध्य रेल का बड़ा जल गुणवत्ता अभियान

2,967 स्थानों की जांच 1,753 टंकियां साफ, 349 नमूनों में नहीं मिला ई. कोलाई

मुंबई, यशभारत। गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के बाद मध्य रेल के मुंबई मंडल ने जल गुणवत्ता को लेकर विशेष अभियान चलाया। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों और कार्यस्थलों पर पानी के स्रोतों और वितरण व्यवस्था की व्यापक जांच की गई।

अभियान के दौरान जल स्रोत, फिल्ट्रेशन संयंत्र, भूमिगत और ऊपरी पानी की टंकियों, जल बूथ, नलों तथा वितरण केंद्रों समेत 2,967 स्थानों की जांच की गई। इनमें 410 कमियां सामने आईं, जिनमें 365 को दूर कर दिया गया है, जबकि 45 पर काम जारी है। 20 अगस्त से 22 सितंबर के बीच मंडल की 2,913 पानी की टंकियों में से 1,753 की सफाई की गई। इसके अलावा 1,716 स्थानों पर वेंट और ओवरफ्लो पाइप पर मजबूत ढक्कन व जालियां लगाई गईं। जल गुणवत्ता की जांच के लिए 349 नमूने लिए गए। भौतिक, रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण में किसी भी नमूने में ई. कोलाई या अन्य बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण नहीं मिला। 134 स्थानों पर रोजाना अवशिष्ट क्लोरीन की निगरानी की जा रही है। सीएसएमटी, कल्याण, भिवंडी रोड और लोनावला में जल पाइपलाइन व्यवस्था की भी जांच की गई। रेलवे के अनुसार, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी का काम आगे भी जारी रहेगा।

सड़क हादसे पर लगेगा तकनीक का ब्रेक

हर 50 किमी पर ट्रॉमा सेंटर
'गोल्डन ऑवर' में मिलेगा तत्काल उपचार

मुंबई, यशभारत। राज्य में सड़क हादसों और दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए परिवहन, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण और स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। दुर्घटना रोकने के लिए आधुनिक तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल, सड़क सुरक्षा ऑडिट और हादसे के बाद घायलों को 'गोल्डन ऑवर' में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाए। यह निर्देश परिवहन मंत्री तथा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने दिए। मंत्रालय में आयोजित 13वीं राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सरनाईक ने कहा कि 'पीएम-राहत' योजना के तहत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अधिकतम सात दिनों तक डेढ़ लाख रुपये तक कैशलेस उपचार उपलब्ध है। उपचार शुरू करने में किसी तरह की देरी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य, पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त कार्यप्रणाली तैयार करें। उन्होंने 108 और निजी एंबुलेंस को एक डिजिटल मंच से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। एंबुलेंस में कैमरा और दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जाएगा, ताकि अस्पताल के चिकित्सक रास्ते में ही मरीज की स्थिति देखकर आवश्यक उपचार संबंधी मार्गदर्शन दे सकें। राज्य में प्रत्येक 50 किलोमीटर के दायरे में सक्षम ट्रॉमा सेंटर विकसित करने की योजना बनाने तथा समृद्धि महामार्ग, द्रुतगति मार्ग, समुद्री मार्ग और दुर्गम क्षेत्रों के लिए हवाई एंबुलेंस नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। सरनाईक ने सड़क निर्माण और रखरखाव के हर चरण में सुरक्षा ऑडिट करने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का 10 प्रतिशत हिस्सा सड़क सुरक्षा के लिए रखने को कहा। हादसों के 'ब्लैक स्पॉट' का वैज्ञानिक विश्लेषण कर वहां सुधार कार्य तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि जनवरी से जुलाई 2026 के बीच पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 6 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2025 में दुर्घटना मृतकों में 60 प्रतिशत दोपहिया वाहन चालक और 22 प्रतिशत पैदल यात्री थे। इसलिए इन दोनों वर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

ठाणे में क्लस्टर योजना को रफ्तार

30 लाख घरों की तैयारी, 6 हजार परिवारों के घर का सपना होगा साकार

ठाणे, यशभारत। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में अगले 15 से 20 वर्षों में 30 लाख नए घर बनाने की योजना है। मुंबई, ठाणे, मीरा-भायंदर, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर समेत विभिन्न शहरों में क्लस्टर पुनर्विकास को गति दी जाएगी। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को सिद्धेश्वर नगर-रमाबाई नगर क्लस्टर योजना के भूमिपूजन समारोह में दी।

शिंदे ने कहा कि क्लस्टर का उद्देश्य सिर्फ नई इमारतें बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण घर के साथ बेहतर सुविधाएं देना है। करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाली परियोजना से लगभग 6 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा। यहां चौड़ी सड़कें, पानी, सीवेज और कचरा प्रबंधन, उद्यान, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, व्यायामशाला, योग केंद्र, डिजिटल पुस्तकालय, डे-केयर सेंटर, वरिष्ठ नागरिक केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत 23 सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने इसे 'सिटी विदिन द सिटी' की अवधारणा बताते हुए आवास के साथ स्थानीय रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही। शिंदे ने 'वॉक टू वर्क' की अवधारणा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ठाणे में क्लस्टर योजना को साकार करने के लिए करीब दो दशक तक प्रयास हुए। किसननगर क्लस्टर का पहला चरण पूरा होने की ओर है और जल्द पात्र निवासियों को घरों की चाबियां देने की बात कही। सिद्धेश्वर तालाब का भी पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

मुंबईकरों को मिलावटी घी परोस रहा था 'गुरुकृपा' का मालिक

सूरजमुखी तेल और वनस्पति घी मिलाकर तैयार किया जा रहा था 'पूजा घी', 15.15 लाख रुपये का माल जब्त

मुंबई, यशभारत। त्योहारी मौसम में घी और मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मालाड पूर्व स्थित मेसर्स गुरुकृपा डेयरी उत्पाद में रिफाइंड सूरजमुखी तेल और वनस्पति घी मिलाकर कथित तौर पर 'पूजा घी' तैयार किए जाने का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान एफडीए ने डेयरी का खाद्य लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया।

जांच में 2,464.05 किलोग्राम घी, सूरजमुखी तेल और वनस्पति घी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 13.55 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा घी बनाने की दो भट्ठी मशीनें और खोवा बनाने की मशीन भी जब्त की गई। मशीनरी समेत कुल 15.15 लाख रुपये का माल कार्रवाई में जब्त हुआ। परिसर में चूहे और तिलचट्टे भी मिले। अंधेरी के मेसर्स गुफरान सीख कॉर्नर में बिना वैध खाद्य लाइसेंस कारोबार चलता मिला। यहां स्वच्छता, भंडारण, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया। एफडीए ने कारोबार बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं, महालक्ष्मी रेसकोर्स स्थित मेसर्स बीजेआरएस (गैलॉप्स) रेस्तरां की रसोई में गंदगी, खून और केचप के दाग, तिलचट्टे, चींटियां और जलभराव जैसी गंभीर खामियां मिलीं। प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है।

बांस से बनेगा इथेनॉल!

27 सितंबर को मुंबई में 'बांस अर्थव्यवस्था' पर मंथन, 50 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य

मुंबई, यशभारत। महाराष्ट्र में बांस को उद्योग, ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। इसी दिशा में मुंबई में 27 सितंबर को 'बांस अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास सम्मेलन-2026' आयोजित किया जाएगा। वेस्टिन मुंबई पवई लेक में होने वाले इस सम्मेलन में बांस से इथेनॉल उत्पादन, जैव ऊर्जा, निर्माण क्षेत्र, कार्बन क्रेडिट, किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

महाराष्ट्र सरकार की बांस उद्योग नीति-2025 के तहत राज्य में करीब 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश, पांच लाख से अधिक रोजगार और 15 बांस औद्योगिक समूह विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपये के उद्यम कोष का भी प्रावधान है। सम्मेलन में निवेशकों, उद्योग जगत, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं की भागीदारी होगी। बांस को निर्माण सामग्री के साथ-साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। बांस से दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल बनाने की तकनीक देश में पहले से इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में बांस आधारित जैव ईंधन उद्योग की संभावनाओं पर भी मंथन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

संपादकीय

आईआईटी की चमक के पीछे घुटता छात्र जीवन

45 मौतें और एक बड़ा सवाल

आईआईटी में आत्महत्या के आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे देश की सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा एक असहज सवाल हैं। पांच साल में 23 आईआईटी में 45 छात्रों ने आत्महत्या की। यानी औसतन लगभग हर डेढ़ महीने में एक छात्र। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे अलग-अलग परिसरों की व्यक्तिगत घटनाओं में बांटकर देखने से असली तस्वीर धुंधली पड़ जाती है। और आंकड़ों का दूसरा पहलू और भी गंभीर है। इन 45 छात्रों में 28 एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से थे—यानी कुल मामलों के 62 प्रतिशत से अधिक। इनमें 12 ओबीसी, नौ एससी और सात एसटी छात्र थे। दूसरी ओर 16 सामान्य वर्ग और एक ईडब्ल्यूएस छात्र था। यह आंकड़ा अपने आप में किसी कारण का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह जरूर बताता है कि सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के सवालों को नजरअंदाज करके समस्या को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता।

साल-दर-साल तस्वीर भी बेचैन करने वाली है। 2022-23 में जहां छह आत्महत्याएं दर्ज हुईं, वहीं 2023-24 में यह संख्या छलांग लगाकर 16 पहुंच गई—यानी एक साल में करीब 167 प्रतिशत की वृद्धि। 2024-25 में भी 13 मौतें हुईं। पांच वर्षों में अकेले आईआईटी हैदराबाद में सात, आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली और कानपुर में छह-छह, मद्रास में पांच और आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी में चार आत्महत्याएं दर्ज हुईं।

इन 45 मौतों के अलावा इसी अवधि में आठ अप्राकृतिक मौतें भी दर्ज हुईं, जिन्हें आत्महत्या के आंकड़े में शामिल नहीं किया गया। यानी परिसर में छात्रों की असामयिक मौतों का दायरा केवल 45 तक सीमित नहीं है।

ऐसे में आईआईटी मुंबई की हालिया घटना को भी केवल एक अलग घटना मानकर भूल जाना आसान रास्ता होगा। परीक्षा में कथित अनियमितता से शुरू हुआ मामला एक युवा जीवन के अंत तक पहुंच गया। यहां अनुशासन और परीक्षा की शुचिता अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या संस्थानों के पास संकट में फंसे विद्यार्थी को संभालने की पर्याप्त व्यवस्था है?

45 आत्महत्याएं किसी एक छात्र की कहानी नहीं, व्यवस्था के सामने रखी गई 45 चेतावनियां हैं। अगर हर मौत के बाद संवेदना व्यक्त करके मामला बंद हो जाता है, तो आंकड़े बढ़ते रहेंगे और कारण हमारी नजरों से छिपे रहेंगे। अब जरूरत आंकड़े गिनने की नहीं, हर आंकड़े के पीछे छिपे सवाल का जवाब खोजने की है।

कड़वे वचन

आदमी जब अपनीलड़कीके लिए लड़का देखने जाता हे तो पत्नी पति से कहती किदो बातों का ध्यान रखना एक लड़का खाते पीते घर का हो। दो मगर खाता पीता नहीं हो। दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है पर समझने वाला इसका मतलब समझता है। फिर पता नहीं क्यों लोग जिंदगी का मतलब नहीं समझते। अरे भाइ जीना है तो जीना (सीढ़ियां) तो चढ़ना ही पड़ेगा।

आज का राशिफल

ज्योतिषाचार्य पंडित लोकेश व्यास

पंचांग:- 24 सितंबर 2026
दिन- गुरुवार, माह- भाद्र शुक्ल पक्ष
विक्रम संवत 2083

मेष (चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ): दिन खुशनुमा रहने वाला है किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है

वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो): पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है धैर्य के साथ आगे बड़े

मिथुन (का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह): आज का दिन व्यापार के लिए कोई नई योजना बनाने के लिए है सफलता मिलेगी

कर्क (ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो): आज का दिन रचनात्मक कार्य करने में व्यतीत होने वाला है अपनी सुख सुविधाओं के सामान पर खर्च कर सकते हैं

सिंह (मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे): दिन बुद्धि व विवेक से निर्णय लेने के लिए रहने वाला है आत्मविश्वास में वृद्धि होगी

कन्या (ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो): विद्यार्थी वर्ग को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करें

तुला (रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते): निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ ले बड़ों की सलाह को मानकर कार्य करें

वृश्चिक (ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे): अजनबियों से सावधानी बरते किसी के भी बहकावे में ना आए

धनु (ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे): दिल लाभदायक रहने वाला है मान सम्मान में वृद्धि होगी

मकर (भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी): अटका हुआ कार्य पूरे होने के संकेत दिख रहे हैं मेहनत करें सफलता मिलेगी

कुंभ (गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा): दिन भर आलस महसूस कर करेंगे कार्य पूरे होने में रुकावटें आ सकती हैं

मीन (दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची): पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा दिन अच्छा व्यतीत करेंगे

हरित खेती का हिसाब खेत से मंडी तक: किसान की जेब में कितना बचा

मौसम अब सिर्फ मौसम नहीं रहा। किसान के लिए यह उसकी फसल का हिसाब है। बारिश कब होगी, कितनी होगी, गर्मी कितनी पड़ेगी और फसल पकने के समय मौसम साथ देगा या नहीं—इन सवालों के जवाब पहले जैसे तय नहीं रहे। किसान जलवायु परिवर्तन को किसी रिपोर्ट या सम्मेलन की भाषा में नहीं समझता। वह इसे खेत में महसूस करता है। कभी फसल के नुकसान में, कभी बढ़ती सिंचाई लागत में और कभी एक ही मौसम में बदलते फैसलों में। 19 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी ह्लत्र्ज्ञ के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के भारत के प्रयासों की तस्वीर सामने रखी। खेती और गांव भी इस तस्वीर का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री के मुताबिक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत करीब साढ़े 12 लाख हेक्टेयर में 24 हजार प्राकृतिक खेती क्लस्टर बनाए जा चुके हैं। उन्होंने करीब तीन हजार जलवायु-अनुकूल फसल किस्में विकसित होने की भी बात कही। जल संरक्षण के संदर्भ में 70 हजार से अधिक अमृत सरोवर और 'कैच द रेन' अभियान के तहत करीब डेढ़ करोड़ वर्षाजल संचयन संरचनाओं का जिक्र भी उनके भाषण में आया। तस्वीर बड़ी है। आंकड़े भी बड़े हैं। लेकिन खेत में खड़े किसान के लिए सवाल थोड़ा अलग है। इन बदलावों से उसकी खेती कितनी बदली?

प्राकृतिक खेती का क्षेत्र बढ़ना एक उपलब्धि हो सकती है। जल संरक्षण के लिए ढांचा खड़ा होना भी जरूरी है। जलवायु के अनुकूल बीज विकसित होना भी समय की जरूरत है। लेकिन किसान के लिए इन सबका मतलब आखिर क्या है?

खेती की लागत कितनी कम हुई?

फसल कितनी सुरक्षित हुई?

और सबसे आखिर में—उसके हाथ में कितना बचा?

यहीं से पर्यावरण की चर्चा किसान की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है। किसान को बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली और मजदूरी का खर्च उठाना पड़ता है। ऊपर से मौसम का जोखिम। ऐसे में प्राकृतिक खेती से अगर बाहरी इनपुट पर निर्भरता घटती है और मिट्टी की सेहत सुधरती है तो यह किसान के लिए राहत हो सकती है। सरकार भी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को लागत कम करने, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने से जोड़ती है। इस मिशन के तहत किसानों को दो वर्षों तक प्रति एकड़ सालाना चार हजार रुपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाता है, अधिकतम एक एकड़ तक। लेकिन किसान के सामने एक और सवाल है कि बदलाव का जोखिम कौन उठाएगा? अगर वह खेती का तरीका बदलता है और शुरुआती दौर में उपज प्रभावित होती है तो क्या होगा? नई पद्धति की जानकारी नहीं है तो कौन साथ खड़ा होगा? और प्राकृतिक तरीके से पैदा की गई फसल बाजार में पहुंचने के बाद क्या सामान्य फसल की तरह ही बिकेगी या किसान को कोई अतिरिक्त लाभ मिलेगा?

ये छोटे सवाल नहीं हैं। इसीलिए प्राकृतिक खेती की बहस को सिर्फ 'रासायनिक बनाम प्राकृतिक' के खांचे में रखना ठीक नहीं होगा। हर इलाके की मिट्टी अलग है। पानी की उपलब्धता अलग है। फसलें अलग हैं। बाजार अलग हैं। किसान की आर्थिक स्थिति भी अलग है। जो तरीका एक इलाके में अच्छा काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वही दूसरे इलाके में भी उसी तरह परिणाम दे। सरकार के स्तर पर भी अब प्राकृतिक खेती को सिर्फ क्षेत्रफल बढ़ने के आंकड़े से देखने के बजाय उसके आर्थिक परिणामों पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 सितंबर की समीक्षा बैठक में किसानों की उत्पादकता, उत्पादन लागत, बाजार मूल्य और शुद्ध आय का तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिए। यानी यह देखने की जरूरत खुद सरकार मान रही है कि प्राकृतिक खेती से किसान को वास्तविक आर्थिक फायदा कितना हो रहा है।

यही बात सबसे महत्वपूर्ण है।

किसान के लिए खेत का आकार नहीं, खेत से बचने वाला पैसा मायने रखता है। कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती की चर्चा को किसान की लागत से जोड़ा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत पर बात की गई है। यह नजरिया बताता है कि खेती के तरीके में बदलाव केवल पर्यावरण का मामला नहीं है। उसके साथ किसान की आर्थिक सुरक्षा भी जुड़ी है।

अब जरा पानी की बात।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे दो करोड़ से अधिक किसानों को पानी बचाने में मदद मिल रही है। पानी बचाना आज सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। कई इलाकों में यह खेती बचाने का सवाल बन चुका है।

यहीं क्करू्यस्रूजैसी योजना का महत्व सामने आता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2 अगस्त 2026 तक कृषि उपयोग के लिए करीब 11.49 लाख ऑफ-ग्रिड सोलर पंप लगाए जा चुके थे और 21.77 लाख से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए थे। योजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना और डीजल पर निर्भरता कम करना भी है। यहां पर्यावरण और किसान की जेब एक साथ दिखाई देती है। अगर सौर ऊर्जा से सिंचाई का खर्च घटता है तो उसका फायदा किसान को है। लेकिन सोलर पंप लगाने की शुरुआती लागत, जमीन और पानी की उपलब्धता और योजना तक पहुंच भी उतने ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। किसी योजना का आंकड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन किसान तक उसकी पहुंच कैसी है, यह अलग सवाल है।

फसल विविधीकरण भी इसी कड़ी का हिस्सा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सरकार का फसल विविधीकरण कार्यक्रम धान जैसी अधिक पानी लेने वाली फसलों से कुछ क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और दूसरी फसलों की ओर ले जाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसका मकसद पानी की बचत के साथ मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करना भी है।

लेकिन यहां फिर वही सवाल लौटता है।

किसान धान छोड़कर दूसरी फसल क्यों लगाएगा?

सिर्फ इसलिए कि वह पानी कम लेती है?

किसान के लिए फसल का बाजार भी उतना ही जरूरी है। अगर वैकल्पिक फसल में पानी कम लगता है लेकिन खरीद की व्यवस्था कमजोर है, कीमत अनिश्चित है या उपज बेचने के लिए दूर जाना पड़ता है, तो किसान के लिए फैसला आसान नहीं होगा। ढ्ढष्ट्रक्रने भी हाल के अध्ययन में अलग-अलग इलाकों में पानी की उपलब्धता, मिट्टी, जलवायु और बाजार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक फसल विविधीकरण पर जोर दिया है। यानी एक ही फार्मूला पूरे देश के लिए नहीं हो सकता।

यही बात जलवायु-अनुकूल फसलों पर लागू होती है। प्रधानमंत्री ने करीब तीन हजार जलवायु-अनुकूल किस्मों के विकास का उल्लेख किया है। बदलते मौसम में ऐसी किस्मों की जरूरत निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन नई किस्म विकसित हो जाना और किसान द्वारा उसे बड़े पैमाने पर अपनाया जाना दो अलग बातें हैं। किसान को बीज, प्रशिक्षण, स्थानीय सलाह और बाजार—चारों चाहिए।

किसान की भाषा में सवाल बहुत सीधा है—

मौसम खराब हुआ तो फसल बचेगी? और फसल बची तो दाम मिलेगा? जल संरक्षण की योजनाओं को भी इसी नजर से देखने की जरूरत है। अमृत सरोवर बने, वर्षाजल संचयन की संरचनाएं बनीं—यह अच्छी शुरुआत है। लेकिन उसके बाद का हिसाब भी होना चाहिए।

(लेखक - निमिषा सिंह)

पाकिस्तान में आतंक का पलटवार

कश्मीर के लिए पाली गई आतंकी फैक्टरी अब पाकिस्तान को ही निगल रही

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में सेना और आतंकियों के बीच करीब 20 घंटे चली मुठभेड़ में आठ आतंकी मारे गए। यह घटना पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही आतंकी हिंसा की उस तस्वीर का हिस्सा है, जिसमें आतंकवादी संगठन लगातार सुरक्षा बलों और नागरिकों के लिए चुनौती बने हुए हैं। कोहाट की घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि आतंकवाद को लंबे समय तक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अब स्वयं उसी आतंक की आग में क्यों झुलस रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से अगस्त 2026 तक पाकिस्तान में 990 आतंकी हमले हुए और इनमें 1126 लोगों की मौत हुई। आठ महीनों के आंकड़े यह बताते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए लगातार बड़ा खतरा बना हुआ है। अगस्त में 199 हमले दर्ज किए गए, जो इस वर्ष के शुरुआती आठ महीनों में किसी एक महीने में सबसे अधिक हैं।

आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी में 87 आतंकी हमले हुए और 105 लोगों की मौत हुई। फरवरी में 83 हमलों में 139 लोगों की जान गई। मार्च में 106 हमलों में 146 मौतें दर्ज की गईं। अप्रैल में 85 हमले हुए और 60 लोगों की मौत हुई। मई में 160 हमलों में 128 लोगों की जान गई। जून में 112 हमले हुए और 118 मौतें दर्ज की गईं। जुलाई में 144 हमलों के साथ 268 मौतें हुईं, जबकि अगस्त में 199 हमलों में 158 लोगों की जान गई।

कश्मीर के नाम पर तैयार आतंक का खेल अब पाकिस्तान पर भारी

पाकिस्तान ने लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर में भारत विरोधी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों को पनाह देने के आरोपों का सामना किया है। कश्मीर को भारत से अलग करने के उद्देश्य से आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल करने की नीति ने लंबे समय तक क्षेत्र में हिंसा को जन्म दिया। आतंकवादियों ने नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और इसके कारण जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी।

लेकिन आतंकवाद की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह जिस दिशा में भेजा जाता है, वहीं तक सीमित नहीं रहता। पाकिस्तान में आज तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूच उग्रवादी संगठन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े गुटों की हिंसक गतिविधियां वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान आतंकवादी हिंसा के प्रमुख केंद्र हैं और इन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को लगातार अभियान चलाने पड़ रहे हैं। कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाएं। कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने जिस आतंकवादी ढांचे को वर्षों तक सहारा दिया, उसका दुष्परिणाम आज पाकिस्तान के भीतर दिखाई दे रहा है। आतंकवादियों ने पाकिस्तान के नागरिकों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया है। जिस आतंकवाद को कभी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल करने का माध्यम समझा गया, वही अब पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने वाला बड़ा कारण बन रहा है।

आतंकवाद को किसी देश की नीति का औजार बनाना अंततः उसी देश के लिए संकट पैदा कर सकता है। जब आतंकवादी संगठनों को संरक्षण, संसाधन या सुरक्षित ठिकाने मिलते हैं तो उनके लिए लक्ष्य की सीमा तय रखना कठिन हो जाता है। एक संगठन दूसरे संगठन से जुड़ता है और अलग-अलग गुट अपने हितों के अनुसार हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान में उभरती आतंकी चुनौती इसी जटिल स्थिति को दर्शाती है।

आंकड़े बता रहे पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद

पाकिस्तान में 2026 के आंकड़ों का सबसे चिंताजनक पहलू हमलों की लगातार ऊंची संख्या है। आठ महीनों में 990 हमलों का अर्थ है कि औसतन हर महीने सौ से अधिक आतंकी घटनाएं दर्ज हुईं। अगस्त में 199 हमलों के साथ हिंसा का आंकड़ा सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। जुलाई में 268 मौतों का आंकड़ा बताता है कि कम संख्या में हुए हमले भी कई बार अत्यधिक घातक साबित हुए। आतंकी हमलों में हुई मौतों और आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा अभियानों में हुई मौतों को अलग-अलग समझना जरूरी है। सुरक्षा अध्ययन संस्थाओं के आंकड़ों में कई बार आतंकवादी हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकियों और सुरक्षा अभियानों में हुई अन्य मौतों को भी व्यापक संघर्ष आंकड़ों में शामिल किया जाता है। इसलिए अलग-अलग रिपोर्टों में कुल मौतों के आंकड़े अलग दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2026 में आतंकी हमलों में 105 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। वहीं आतंकवादी हिंसा और सुरक्षा अभियानों को मिलाकर व्यापक संघर्ष आंकड़ा 361 मौतों तक पहुंचा था। इसमें 242 आतंकी, 73 नागरिक और 46 सुरक्षा बलों के जवान शामिल बताए गए। जुलाई में आतंकवादी हिंसा और सुरक्षा अभियानों को मिलाकर 606 मौतों का आंकड़ा सामने आया। इनमें 401 आतंकी, 112 सुरक्षा बलों के जवान, 74 नागरिक और 19 शांति समितियों से जुड़े लोग शामिल थे। वर्ष 2026 के शुरुआती चार महीनों में भी पाकिस्तान में 401 आतंकी हमले दर्ज किए गए थे। इस अवधि में 190 नागरिकों और 158 सुरक्षा बलों के जवानों की मौत का आंकड़ा सामने आया। सुरक्षा अभियानों में 988 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी भी दी गई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद केवल हमलों की संख्या का विषय नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ चल रहे सैन्य और सुरक्षा अभियानों ने भी देश के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद से दूसरे सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में रखा गया था। रिपोर्ट में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की हिंसक गतिविधियों में बड़ी वृद्धि का उल्लेख किया गया था। 2024 में इस संगठन से जुड़े 482 हमलों में 558 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया गया था।

(लेखक - कांतिलाल मांडोत)

भारत को डराया नहीं जा सकता, यह नया भारत है

हाल ही में अमेरिकी संसद द्वारा भारत एवं चीन सहित कुछ अन्य देशों से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने सम्बंधी कानून को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, क्योंकि, ये देश रूस से कच्चे तेल का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं। अमेरिका के अनुसार, इन देशों द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात के चलते रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध करने की आर्थिक शक्ति प्राप्त हो रही है। जबकि, यूरोपीयन देश एवं अमेरिका स्वयं रूस से गैस एवं अन्य उत्पादों का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं। अर्थात, इन देशों द्वारा रूस से अन्य पदार्थों के आयात करने से रूस को कोई आर्थिक ताकत प्राप्त नहीं होती है, केवल भारत एवं चीन सहित कुछ अन्य देशों द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात से रूस को आर्थिक शक्ति प्राप्त होती है। अमेरिका का यह दोहरा चरित्र अब पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित हो रहा है। अमेरिका को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर 100 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का डर दिखा कर एवं भारत को दबाव में लाकर अमेरिका भारत से अपने मनमाफिक निर्णय करवा लेगा, तो आज की बदली हुई परिस्थितियों के बीच यह सम्भव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका एवं पूरे विश्व के सामने अब एक नया भारत खड़ा है। अमेरिका दरअसल चाहता है कि भारत उसके कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोले ताकि वह भारत को अपने कृषि एवं डेयरी उत्पाद निर्यात कर सके। यदि भारत अमेरिका के इस दबाव में आता है तो भारतीय किसानों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और केंद्र सरकार भारत के किसानों के हितों की बलि किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। आज, संभवत~ अमेरिका को भारत की अधिक आवश्यकता है क्योंकि भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है, जिसके कारण भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देशों की श्रेणी में उच्च स्थान रखता है। साथ ही, भारत आज विश्व में विभिन्न उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है एवं आगे आने वाले समय में भारत की यही स्थिति लम्बे समय तक बनी रहने वाली है। भारत आज विश्व के अन्य उत्पादक देशों के लिए सबसे बड़ा बाजार है।

भारत का सकल घरेलू उत्पाद आज विश्व में बड़े देशों के बीच सबसे अधिक तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जापान ने भारत की सार्वभौमिक क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। और तो और, अब अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियां भी भारत की सार्वभौमिक क्रेडिट रेटिंग में सुधार करने पर विचार करने को मजबूर हो रही हैं। हाल ही में मूडीज ने वर्ष 2026 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही, जेफरीज ने भी अपने पूर्व अनुमान 6.7 प्रतिशत को सुधारकर 7 प्रतिशत कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को 6.7 प्रतिशत कर दिया है, जबकि भारत ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में 7.8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल की है।

भारत के अपने विदेशी उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने सम्बंधित प्रयास आज सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि, अगस्त 2026 का माह भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत शानदार रहा है। वैश्विक स्तर पर कई प्रकार की चुनौतियों के चलते भी भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में 26.12 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर्ज हुई है। अगस्त 2025 माह में भारत के कुल निर्यात 3,474 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे थे जो अगस्त 2026 में बढ़कर 4,381 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हो गए हैं। फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आरगनाईजेशन के अनुसार, भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में हो रही आकर्षक वृद्धि दर भारतीय निर्यातकों की ताकत, प्रतिस्पर्धा व बाजार के हिसाब से ढलने की क्षमता को दर्शाती है। चीन, सिंगापुर, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, तंजानिया, हांगकांग, आस्ट्रेलिया, स्पेन एवं श्रीलंका जैसे बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती पहुंच भारत के निर्यात बास्केट के विस्तार का संकेत है। आटोमोबाईल निर्यात में 22.2 प्रतिशत की मजबूत बृद्धि दर्ज हुई है, इसमें दोपहिया व तिपाहिया वाहनों का दबदबा रहा है। जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात में भी 3.14 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं इंजीनीयरिंग उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि भारत की मजबूत स्थिति को दर्शा रही है।

विदेशी व्यापार के मामले में भारत विश्व में केवल कुछ देशों (अमेरिका सहित) पर निर्भर रहने के स्थान पर अब अपने विभिन्न उत्पादों के निर्यात के लिए नए नए बाजार तलाश रहा है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों का सुपरिणाम दिखाई भी देने लगा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम पांच माह (अप्रेल-अगस्त 2026) के दौरान भारत का ब्रिक्स देशों (चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं रूस) को निर्यात 34 प्रतिशत बढ़कर 1,990 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है। इसी अवधि में चीन को भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई हैं। ब्रिक्स समूह के समस्त सदस्य देशों के साथ भारत अपने आर्थिक एवं राजनैतिक सम्बंध लगातार मजबूत कर रहा है, जिसका परिणाम अब इन देशों के साथ भारत के लगातार बढ़ रहे विदेशी व्यापार के रूप में दिखाई देने लगा है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, ब्रिक्स के चार मुख्य देशों (चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं रूस) का भारत के कुल निर्यात में हिस्सा अप्रेल-अगस्त 2025 के दौरान 8.1 प्रतिशत से बढ़कर अप्रेल-अगस्त 2026 के दौरान 9.2 प्रतिशत हो गया है। इस वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच माह के दौरान चीन को 960 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया है तो वहीं दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील एवं रूस को भारतीय उत्पादों के निर्यात में क्रमशः 58 प्रतिशत, 13 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर्ज की गई है।

आज कई अमेरिकी कम्पनियां भारत में अपने वैश्विक योग्यता केंद्रों की स्थापना कर रही हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं - एस्ट्रा जेनेका, बैंक ओफ अमेरिका, ट्रूब्रिज, गाइडवायर, आदि। भारत में स्थापित इन वैश्विक योग्यता केंद्रों में हजारों की संख्या में भारतीय इंजीनीयर कार्य कर रहे हैं। कहीं यह अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगातार बदले जा रहे वीजा सम्बंधी नियमों के चलते तो नहीं हो रहा है।

(लेखक- प्रहलाद सबनानी)

रात 10 बजे से सो जाती है रेलवे की टिकट व्यवस्था..!

मदन महल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म-4 की टिकट विंडो हो जाती है बंद, ट्रेन पकड़ने से पहले यात्रियों को लगानी पड़ रही प्लेटफॉर्म-1 की दौड़

जबलपुर, यशभारत। मदन महल रेलवे स्टेशन पर रात के समय यात्रियों की परेशानी रेलवे की टिकट व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। रात 10 बजे प्लेटफॉर्म-4 की टिकट विंडो बंद हो जाने के बाद इस प्लेटफॉर्म से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को टिकट लेने के लिए प्लेटफॉर्म-1 की ओर चक्कर लगाना पड़ता है। खास बात यह है कि रात के समय मदन महल से गुजरने वाली कई ट्रेनों को प्लेटफॉर्म-3 और 4 पर लिया जाता है, ऐसे में टिकट लेने की यह व्यवस्था यात्रियों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं रह जाती।

ट्रेन प्लेटफॉर्म-4 पर, टिकट प्लेटफॉर्म-1 पर!

रात में जब यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म-4 पर पहुंचते हैं, तो उन्हें टिकट खिड़की बंद मिलती है। इसके बाद टिकट लेने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म-1 की ओर जाना पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि यदि ट्रेन का समय नजदीक हो तो प्लेटफॉर्म बदलने और टिकट लेने की इस कवायद में ट्रेन छूटने का खतरा बना रहता है। कई यात्री जल्दबाजी में बिना टिकट यात्रा करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ की ट्रेन ही छूट जाती है।

एक नंबर पर जनशताब्दी का 'डेरा', बाकी यात्री परेशान

मदन महल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म-1 पर जनशताब्दी एक्सप्रेस रोजाना रात 10.45 से सुबह 5.40 तक खड़े रहने के कारण कई ट्रेनों को प्लेटफॉर्म-3 और 4 पर लिया जा रहा है। ऐसे में रेलवे के परिचालन प्रबंधन और टिकट व्यवस्था के बीच तालमेल का अभाव यात्रियों पर भारी पड़ रहा है। इस व्यवस्था का सबसे अधिक खामियाजा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए उन्हें अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। उम्रदराज यात्रियों के लिए रात में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना आसान नहीं है। यदि टिकट लेने के बाद ट्रेन पकड़ने के लिए दोबारा प्लेटफॉर्म-4 पहुंचना हो तो परेशानी और बढ़ जाती है।

रेलवे की व्यवस्था पर यात्रियों का सवाल

यात्रियों का कहना है कि यदि रात में प्लेटफॉर्म-4 से नियमित रूप से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है तो वहां टिकट सुविधा भी ट्रेन संचालन के समय तक उपलब्ध रहनी चाहिए। कम से कम उन ट्रेनों के समय के अनुरूप टिकट विंडो का संचालन किया जाना चाहिए, जिनका ठहराव प्लेटफॉर्म-3 और 4 पर निर्धारित है। विडंबना यह है कि रेलवे यात्रियों को समय पर ट्रेन पकड़ने की सलाह देता है, लेकिन मदन महल स्टेशन पर रात में टिकट लेने के लिए ही यात्रियों को प्लेटफॉर्मों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेलवे की टिकट व्यवस्था यात्रियों की सुविधा के हिसाब से चलेगी या फिर यात्री ही व्यवस्था के हिसाब से दौड़ते रहेंगे..?

क्या कहते हैं अधिकारी ..

मदन महल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार में यात्रियों को रही इस समस्या पर जल्द विचार कर समस्या का निदान किया जायेगा। वैसे मशीन लगी हुईं हैं और यात्री रेल वन एप से भी टिकट निकाल सकते हैं।

***शशांक गुप्ता,** सीनियर डीसीएम जबलपुर मंडल*

जीसीएफ उत्पादन में पिछड़ी, मुख्यालय ने जताई गहरी चिंता

1900 करोड़ रुपए का लक्ष्य, आधा साल बीतने को 250 करोड़ का हो पाया काम

जबलपुर यश भारत। **शहर की सबसे पुरानी निर्माणी गन केरिज फैक्ट्री यानि जीसीएफ जिसके जिम्मे सेना को महत्वपूर्ण अस्त्रों की आपूर्ति करना है।इस सत्र यानि 2026-27 में अपने उत्पादन लक्ष्य से बहुत दूर है। बताया जाता है कि अब तक उत्पादन करीब 13 फीसदी ही हो पाया है।इसको लेकर एडवांस वेपन एन्ड इक्यूपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी(AWEIL) के कानपुर स्थित मुख्यालय ने गहरी चिंता जताई है और कहा है कि 30 सितंबर को समाप्त हो रही दूसरी तिमाही तक उत्पादन पूरा करने की कोशिश की जाए।**

क्योंकि इसकी जानकारी दिल्ली स्थित वरिष्ठ एजेंसियों को दी जाना है।मुख्यालय से आये इस संदेश के बाद सबके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। उल्लेखनीय है कि जीसीएफमें सेना के लिए महत्वपूर्ण धनुष तोप और एल एफ जी के साथ टी सिरीज टेंक के महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले सत्र में भी जीसीएफको अच्छा खासा उत्पादन लक्ष्य मिला था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। फलस्वरूप बीते सत्र का भी उत्पादन मिला कर इस सत्र में लगभग 1968.75 करोड़ रुपए का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है । अधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब तक 264करोड़ रुपए का ही उत्पादन हो पाया है। जबकि सत्र के 6 माह गुजर चुके हैं। मुख्यालय से 21 सितंबर को आये संदेश में कहा गया है कि संशोधित प्रतिबद्धता के अनुसार 30 सितंबर तक 421 करोड़ रुपए का उत्पादन हो जाना चाहिए ।लेकिन अब तक मात्र 264.54 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। जो अत्यंत चिंतनीय है। जानकारों के अनुसार निगम में आने के बाद निर्माणी संक्रमण काल से गुजर रही है। दिनों दिन मानव कार्य बल कम होता जा रहा है। मानित प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की संख्या सेवा निवृत्ति के चलते कम हो रही है। दूसरी ओर अब तक निगम की एच आर पालसी तैयार नहीं हो सकी है। ऐसे में उत्पादन पूरा करने के लिए तदर्थ रूप से एक मुश्त वेतन पर एक वर्ष के लिए दक्ष कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। जिनकी अधिकतम नियुक्ति 4 वर्ष के लिए तय की गई है। इन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान भविष्य में कोई वेतन, पदोन्नति आदि अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रावधान नहीं है। जिसके चलते संशोधित प्रतिबद्धता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है।

इनका कहना है

निर्माणी के सभी अधिकारी, कर्मचारी पूरे मनोयोग से उत्पादन लक्ष्य के लिए जुटे हैं। उत्पादन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि सत्र समाप्ति तक हम लक्ष्य से अधिक उत्पादन करेंगे।

***राहुल चौधरी,** जन संपर्क अधिकारी जीसीएफजबलपुर*

कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिरी, घटना में बाल-बाल बचा परिवार

पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार

जबलपुर,यशभारत। घमापुर थाना क्षेत्र के बरउ मोहल्ला में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभराकर धराशाई हो गई। हादसे के समय परिवार के सदस्य मकान के अंदर सो रहे थे। दीवार गिरने की तेज आवाज सुनकर परिवार के लोग घबरा गए और किसी तरह सुरक्षित बाहर निकले। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया।

दीवार के मलबे में मकान के अंदर रखा गृहस्थी का सामान दब गया, जिससे परिवार को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अचानक हुए हादसे के बाद परिवार के सामने घर को सुरक्षित करने और जरूरी सामान बचाने की समस्या खड़ी हो गई है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर परिवार की मदद की और मलबा हटाने में सहयोग किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि मकान

की हालत पहले से ही जर्जर थी और दीवार काफी कमजोर हो चुकी थी। इसके बावजूद परिवार इसी मकान में रहने को मजबूर था। देर रात अचानक दीवार गिरने से पूरा परिवार दहशत में आ गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने भी प्रशासन से जर्जर मकानों की स्थिति का जायजा लेने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन कराने के साथ ही आर्थिक सहायता और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की मांग की है।

रोड पर नशे में मिली युवती का हाई-वोल्टेज ड्रामा, ऑटो चालक पर मारपीट का आरोप

जबलपुर,यश भारत। रांझी थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा मोहल्ला स्थित परशुराम रोड पर बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती नशे की हालत में सड़क

के बीच पड़ी मिली। स्थानीय लोगों ने जब युवती से पूछताछ की तो उसने हंगामा करते हुए लोगों से गाली-गलौज शुरू कर दी। युवती ने आरोप लगाया कि एक ऑटो चालक ने उसे शराब पिलाने के बाद उसके साथ मारपीट की और सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवती खुद को रानीताल स्थित सुभाष मेडिकल के पास रहने वाली बता रही थी। घटना की सूचना मिलते ही रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने पुलिस टीम को तत्काल मौके पर भेजा। पुलिस ने युवती से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी जुटाने का प्रयास किया।

भोपाल में सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

रहवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

भोपाल, यश भारत । राजधानी में सीलिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कार्रवाई के पालन में लापरवाही पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रहवासी क्षेत्रों में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जहां सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश लागू हैं, वहां उनका सख्ती से पालन होना चाहिए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पांच बिंदुओं में निर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि जिन क्षेत्रों का भूमि उपयोग स्पष्ट नहीं है अथवा जहां मिश्रित भूमि उपयोग की स्थिति है, उन्हें सीलिंग की कार्रवाई से अलग रखा जाए। हालांकि, स्पष्ट रूप से रहवासी उपयोग वाले क्षेत्रों में कार्रवाई नहीं रोकी जाए। सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुरूप जारी रखने को कहा गया। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से गठित कमेटी को लेकर अवमानना के मामले में

अदालत के एमिकस क्यूरी ए.के. सिन्हा ने जांच की थी। सुनवाई में सिन्हा ने अदालत को बताया कि कमेटी गठित कर सरकार ने अदालत के आदेश की अवमानना की है।

इस पर मध्यप्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ता के.एन. नटराजन ने अदालत को बताया कि सरकार से इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे ऐसी कोई कमेटी गठित नहीं की जाएगी और सीलिंग की कार्रवाई को भी बाधित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आश्वासन को स्वीकार कर लिया। हालांकि, अवमानना के संबंध में अंतिम स्थिति लिखित आदेश सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

सुबह सीलिंग, शाम को खुल रहे प्रतिष्ठान

सुनवाई से पहले शुक्रवार सुबह भोपाल के करीब 10 रहवासियों की शिकायतें एमिकस क्यूरी के माध्यम से अदालत के सामने रखी गईं। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ स्थानों पर सुबह सीलिंग की कार्रवाई होती है, लेकिन शाम तक संबंधित प्रतिष्ठान फिर से खुल जाते हैं।

इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई स्थानों पर निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है, विशेष रूप से भोपाल में। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां सीलिंग कार्रवाई के सख्त निर्देश हैं, वहां उनका पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।

1995 के बाद नया मास्टर प्लान नहीं

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भोपाल के मास्टर प्लान का मुद्दा भी रखा गया। अधिवक्ता के.एन. नटराजन ने बताया कि भोपाल के लिए 1995 के बाद नया मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है और पिछला मास्टर प्लान वर्ष 2005 में समाप्त हो चुका था। सरकार ने अदालत को बताया कि नए मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार है और अब उसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मास्टर प्लान के प्रारूप को जारी करने के संबंध में हरी झंडी दे दी।

अब 29 सितंबर को होगा एफआईआर पर फैसला

निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई

कटनी, यशभारत। हत्या के आरोपी की जमीन हड़पने के मामले में आरोपी फरार निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय करते हुए इसे अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को जस्टिस हिमांशु जोशी की सिंगल बेंच में प्रस्तावित थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं, इसलिए इसका विचारण उपयुक्त संबंधित बेंच द्वारा किया जाना चाहिए। हालांकि नेहा के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि ये धाराएं पिछली सुनवाई के बाद जोड़ी गई हैं और मामला पुरानी तय बेंच में ही सुना जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद मामले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई करने वाली उपयुक्त डिवीजन बेंच माननीय न्यायमूर्ति आनंद पाठक एवं माननीय न्यायमूर्ति रामकुमार चौबेद्ध के समक्ष भेज दिया। विदित हो कि सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने एफआईआर को बेबुनियाद बताते हुए इसे चुनौती दी है और अंतरिम राहत की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई सीधे सबूत मौजूद नहीं हैं और एफआईआर में उनकी सीधी भूमिका नहीं दर्शाई गई है।

पुणे से जबलपुर के लिए निकली महिला रहस्यमय ढंग से गायब

पीड़ित परिजन शिकायत लेकर भटक रहे दर-दर

जबलपुर यशभारत। पुणे से 19 सितंबर को ट्रेन से जबलपुर के लिए एक महिला जब नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने तलाश शुरू की गई।

जानकारी के अनुसार कुंडम निवासी वंदना चौधरी उम्र 23 वर्ष 19 सितंबर को पुणे से ट्रेन के जरिए जबलपुर के लिए रवाना हुई 20 सितंबर को सुबह 9:00 बजे परिजनों से फोन पर बात के दौरान उसने बताया कि वह इटारसी पहुंच रही है इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और वह जबलपुर नहीं पहुंची इसके बाद परिजन स्टेशन पहुंचे जहां पर जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर जबलपुर आने वाली ट्रेन के फुटेज परिजनों को दिखाएं लेकिन उसमें महिला नजर नहीं आई परिजनों का आरोप है कि रेल पुलिस ने जब शिकायत दर्ज नहीं की तो परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और जब महिला के मोबाइल की लोकेशन निकाली गई तो लोकेशन सिहोरा के पास मिली। जिसके आधार पर परिजन लोकेशन पर पहुंचे लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजन सिहोरा थाने पहुंचे तो सिहोरा पुलिस ने आवेदन लिया लेकिन रिसीविंग नहीं दी महिला वंदना चौधरी का विवाह सिहोरा के पास स्थित ग्राम पौडा में हुआ था। और वह अपने पति के साथ पुणे में प्लास्टिक कंपनी में काम करती थी और एक माह पूर्व पति सिहोरा आ चुका था। महिला एक माह बाद पुणे से जबलपुर के लिए रवाना हुई थी महिला का पति और उसके परिजन महिला की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं।

25 से पांच दिनों के लिए बैंकों में ताले

जबलपुर, यशभारत। जबलपुर के बैंक खाताधारकों और व्यापारियों के लिए आने वाले दिन बेहद परेशानी भरे साबित हो सकते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने अपनी मांगों को लेकर 28 से 30 सितंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 को रविवार का अवकाश रहेगा। इस तरह लगातार 5 दिनों तक बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। जबलपुर जिले की लगभग 250 शाखाओं में शनिवार से बुधवार तक ताले लटके रहेंगे। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बरोदा और केनरा बैंक समेत सभी प्रमुख सार्वजनिक बैंक इस हड़ताल में शामिल रहेंगे। चेक क्लियरिंग बंद रहने से मंडी, सराफा और कपड़ा बाजार का व्यापार प्रभावित होगा, वहीं ड्राफ्ट, लॉकर और कैश ट्रांसफर जैसी सेवाएं पूरी तरह थम जाएंगी। बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों को 25 सितंबर तक जरूरी काम निपटाने की सलाह दी है।

राजुल टाउनशिप में शराब के नशे में मजदूरों से मारपीट

गोराबाजार पुलिस ने दर्ज किया मामला

जबलपुर,यशभारत। बिलहरी स्थित निर्माणाधीन राजुल टाउनशिप में शराब के नशे में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि टाउनशिप में रहने वाले बाबी और उसके साथियों ने वहां मजदूरी कर रहे तीन मजदूरों से विवाद के बाद उनके साथ जमकर मारपीट की। अचानक हुए हमले से मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। मारपीट में तीनों मजदूर घायल हो गए।

बताया जा रहा है कि घायल मजदूर सागर जिले के रहने वाले आदिवासी हैं और राजुल टाउनशिप में रहकर मजदूरी कर रहे थे। मजदूरों के मुताबिक, देर रात आरोपी शराब के नशे में उनके पास पहुंचे और किसी बात को लेकर विवाद करने लगे। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने तीनों मजदूरों को घेर लिया और लात-घूंसों से हमला कर दिया। हमले में मजदूरों के हाथ-पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। मारपीट के बाद घायल मजदूर किसी तरह पुलिस के पास पहुंचे और घटना की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस अब घटना की वजह और मारपीट में शामिल आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। नर्माणाधीन टाउनशिप में मजदूरों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद वहां काम कर रहे अन्य मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मजदूरों ने पुलिस और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफकार्रवाई करने तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

पावर कट से पावर सरप्लस बना मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री यादव

भोपाल, यश भारत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश पावर कट से पावर सरप्लस स्टेट बन चुका है और आज प्रदेश अपनी ऊर्जा जरूरतों से आगे बढ़कर देश की ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को होटल मैरिएट में आयोजित ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 32 हजार मेगावाट की ऊर्जा क्षमता है जिसमें करीब 30 प्रतिशत हिस्सा क्लीन एनर्जी का है। राज्य सरकार सस्ती और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराने के साथ उत्पादन एवं ऊर्जा भंडारण की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि नीमच-मंदसौर में 2000 मेगावाट क्षमता की परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सौर पवन और ऊर्जा भंडारण का संतुलित मिश्रण विकसित कर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार को रोकना जरूरी है।

नियम और कंपनी पर आधारित होता है नोटिस पीरियड

नई दिल्ली, एजेंसी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नौकरी काफी अच्छी मानी जाती है। अच्छी सैलरी के साथ कई तरह की सुख-सुविधाएं भी मिलती हैं हालांकि उससे बेहतर ऑफर मिल जाने पर लोग वहां की नौकरी भी छोड़ देते हैं। क्या होता है कंपनी नोटिस पीरियड किसी कंपनी से रिजाइन करने के बाद एंप्लॉई को नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। नोटिस पीरियड नियम कंपनी और देश के श्रम कानूनों पर निर्भर करते हैं। ये नियम कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों के लिए लागू हो सकते हैं। इन नियमों के बारे में करार में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। आमतौर पर हर कंपनी अपने नियम खुद सेट करती है पर कुछ नियम लगभग हर रजिस्टर्ड कंपनी पर लागू होते हैं. जानिए नोटिस पीरियड के कुछ ऐसे सामान्य नियम, जो सभी कंपनियों पर लागू हैं.

अवधिः

नोटिस पीरियड की अवधि आमतौर पर 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक हो सकती है। यह आपके पद, अनुभव और कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करता है. उदाहरण- जूनियर लेवल के लिए 30 दिन, सीनियर लेवल के लिए 60 दिन.

लिखित सूचनाः

नौकरी छोड़ने की सूचना आमतौर पर लिखित रूप में (ईमेल या रिजाइनेशन लेटर) के जरिये देनी होती है। इसमें नोटिस पीरियड शुरू होने की तारीख और लास्ट वर्किंग डे की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इससे बाद में किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है।

काम करनाः

नोटिस पीरियड के दौरान सामान्य रूप से काम करना पड़ता है, जब तक कि कंपनी आपको पहले रिलीव न कर दे। वहीं कुछ मामलों में, कंपनी एक विकल्प दे सकती है, जहां आपको काम नहीं करना पड़ता पर आप तकनीकी रूप से अभी भी कर्मचारी रहते हैं.

सैलरीः

नोटिस पीरियड के दौरान भी पूरी सैलरी मिलती है। अगर आप नोटिस पीरियड पूरा नहीं करते हैं तो कंपनी आपसे उस अवधि की सैलरी वापस मांग सकती है। इसे आमतौर पर नोटिस पीरियड बाईआउट कहा जाता है.

कानूनी बाध्यताः

भारत जैसे देशों में, श्रम कानून नोटिस पीरियड को नियंत्रित करते हैं। अगर अनुबंध में लिखा है तो उसे मानना जरूरी होता है। यह बात कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों पर लागू होती है। इसमें सामान्य रुप से नोटिस पीरियड एक माह का होता है।

बारहवीं के बाद इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और संस्थानों से करें एआई कोर्स

__नई दिल्ली, एजेंसी।__ आजकल छात्रों के बीच एआई सर्टिफिकेट कोर्स की मांग बढ़ रही है। दरअसल एआई के तेजी के विकास के साथ इसमें नौकरी के अवसर तो बढ़े ही साथ ही इस विषय के प्रति छात्रों का रुझान भी बढ़ा है। जहां पहले एआई कोर्स स्नातक छात्रों के बीच लोकप्रिय थे, अब यह कोर्स स्कूली छात्रों के बीच भी अधिक लोकप्रिय हो रहे है। ऐसे में अगर आप भी एआई कोर्स करके अपने कौशल और रचनात्मकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों से भी एआई में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। एआई कोर्स करने से आपको न केवल नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे, बल्कि आप इस कोर्स को करके अधिक वेतन वाली नौकरी भी हासिल कर सकते हैं।

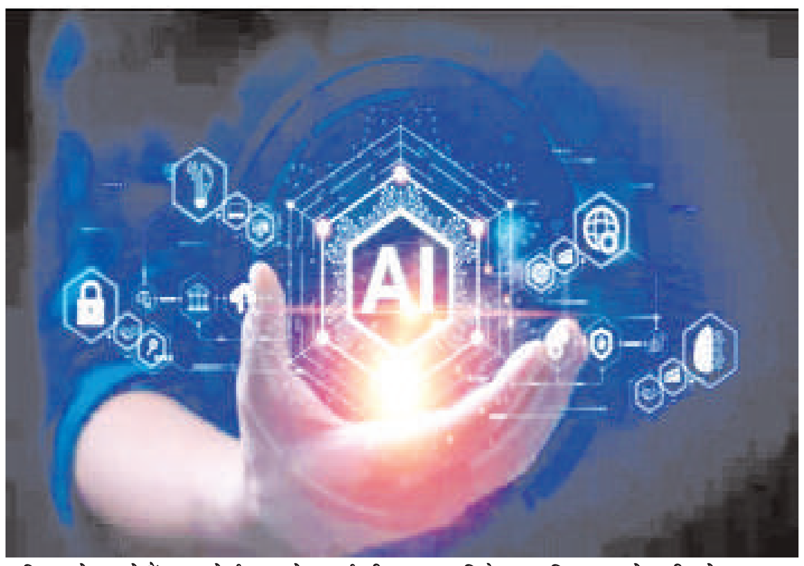

आईआईटी मद्रास के कोर्स

आईआईटी मद्रास ने छात्रों के लिए स्वयं पोर्टल पर एआई पर आधारित पांच ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है। इस कोर्स की खास बात ये है कि इन कोर्स में किसी भी स्ट्रीम के छात्र शामिल हो सकते हैं। साथ ही इन कोर्सेज की अवधि 25 से 45 दिन निर्धारित की गई है।

आईआईटी हैदराबाद

अगर आपको एआई में रुचि है, तो आप आईआईटी हैदराबाद से कक्षा बारहवीं के बाद बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। यह कोर्स आपको एआई की बारीकियों से अवगत करेगा। साथ ही चार साल के इस इस कोर्स को करके आप किसी संस्थान से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं।

आईआईटी मंडी

अगर आप एआई के क्षेत्र में अपने कौशल और ज्ञान को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो आप स्नातक के बाद आईआईटी मंडी से डेटा साइंस एंड एआई कोर्स में भी शामिल हो सकते है। यह दो साल का कोर्स चार सेमेस्टर में विभाजित है। इस कोर्स में शामिल होकर आपको न केवल एआई की तकनीकी से अवगत कराया जाएगा, बल्कि आप अपनी कम्यूनिकेशन स्किल को भी बेहतर कर सकेंगे।

स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म

अगर आप बारहवीं पास छात्र हैं और एआई कोर्स का रुख करना चाहते हैं, तो आप स्वयं पोर्टल के अलावा, स्किल इंडिया से भी एआई कोर्स कर सकते हैं। साथ ही कोर्सेरा, हार्वर्ड, और स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कोर्स में भी शामिल हो सकते हैं। इन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एआई व एमएल कोर्स फ्री में उपलब्ध है। साथ ही इन कोर्स को पूरा करके आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं।

दुनियाभर में हेल्थकेयर पेशेवरों की मांग बढ रही

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनियाभर में हेल्थकेयर पेशेवरों की मांग बढ़ती जा रही है। मंदी के दौर में भी इस सेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता है। हर साल करोड़ों छात्र एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस जैसे कोर्स की पढ़ाई करने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इसी कारण दुनिया भर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ती जा रही है पर इसमें भी भारत पहले नंबर पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज भारत में हैं। भारत में मेडिकल एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। साल 2024 तक, भारत में कुल 780 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए थे। इसमें सरकारी और निजी, दोनों शामिल हैं। यह संख्या 2014 से पहले 387 थी, जो अब 102 फीसदी की दर के साथ 780 तक पहुंच गई है। भारत में हर साल करीब 1,18,137 एमबीबीएस ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं। यह आंकड़ा 2024 के अनुसार है, जब मेडिकल सीटों की संख्या 51,348 (2014 से पहले) से बढ़कर 1,18,137 हो गई थी यानी 130 फीसदी की वृद्धि इसमें सिर्फ एमबीबीएस शामिल है। अगर पोस्टग्रेजुएट (एमडी और एमएस) को जोड़ा जाए तो संख्या और बढ़ जाएगी। वहीं साल 2022-23 में पीजी सीटें 64,059 थीं। एमबीबीएस की सीटें सरकारी और निजी कॉलेजों में बंटी हुई हैं। निजी मेडिकल कॉलेज की फीस सरकारी कॉलेज की तुलना में ज्यादा होती है। एमबीबीएस सीटें- 1,18,137 (2024 तक). भारत के तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मेडिकल कालेज 74 हैं वहीं इसमें लगभग 11,000 से अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 68 कॉलेज, सीटें लगभग 9,000 से अधिक हैं। कर्नाटक में 70 कॉलेज में 11,745 से अधिक सीटें हैं। वहीं चीन में 2018 तक चीन में 420 मेडिकल संस्थान थे। वहां हर साल लगभग 4,00,000 डॉक्टर तैयार होते हैं। कॉलेजों की संख्या भारत से कम है, लेकिन उनकी आबादी (1.4 अरब) और बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण के कारण डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है।

बीबीए या बीसीए के साथ इंटीग्रेटेड एलएलबी करें

नई दिल्ली, एजेंसी। 12वीं के बाद अगर आप वकालत लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बीबीए+एलएलबी या बीसीए+एलएलबी जैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बीसीए का बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशंस है। अब इन दो कोर्सेस के साथ एलएलबी की डिग्री भी ले सकते हैं। समय के साथ ही करियर विकल्प भी बदलते जा रहे हैं। अब छात्रों के पास एक ही फील्ड में कई करियर विकल्प होते हैं। आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेस का चलन बढ़ा है। इन कोर्सेस में दो अलग-अलग डिग्रियों की पढ़ाई एक साथ होती है। कोर्स खत्म होने के बाद स्टूडेंट को दोनों की मिलाकर एक डिग्री दी जाती है। अगर आप बीबीए या बीसीए के साथ लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो जानिए कुछ बेस्ट ऑप्शन. बीबीए, बीसीए लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स (पांच साल) बीबीए एलएलबी -इस इंटीग्रेटेड कोर्स में बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ की पढ़ाई एक साथ होती है। इसमें बिजनेस से जुड़े विषयों (मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर) के साथ-साथ कानून के मूल सिद्धांत (कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ) पढ़ाए जाते हैं। बीबीए और बीसीए के बाद लॉ (3 साल का एलएलबी) बीबीए या बीसीए कोर्स पूरा करने के बाद भी 3 साल का एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा है, जो पहले बिजनेस या टेक्नोलॉजी में बेस बनाना चाहते हैं और फिर कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं। बीबीए के बाद- कॉर्पोरेट लॉ या बिजनेस लॉ में विशेषज्ञता ले सकते हैं। बीसीए के बाद- साइबर लॉ, डेटा प्राइवेसी लॉ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में करियर बना सकते हैं। स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स बीबीए/बीसीए के साथ या बाद में आप लॉ से जुड़े शॉर्ट-टर्म कोर्स कर सकते हैं, जैसे- 1- साइबर लॉ (बीसीए के लिए) 2- कॉर्पोरेट लॉ (बीबीए के लिए) 3- इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (आईपीआर) यह कोर्स 6 महीने से 1 साल के हो सकते हैं और ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में उपलब्ध हैं. लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन इस प्रकार मिलेगा बीबीए एलएलबी के लिए एलिजिबिलिटी- 12वीं पास (किसी भी स्ट्रीम से), कम से कम 45-50 फीसदी अंकों के साथ. कुछ कॉलेज में मैथ्स होना अनिवार्य हो सकता है. प्रवेश परीक्षा कलेट टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए. एआई एलईटी एलऐट प्राइवेट लॉ कॉलेज के लिए. एमसी सीईटी महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए. प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद ही कालेजों में प्रवेश मिलेगा।

एआई निवेश से वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 2026 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर पार करेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में बढ़ते निवेश से वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार को तेज गति मिल रही है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक यह बाजार 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। यह अनुमान पहले लगाए गए अनुमानों से करीब डेढ़ गुना अधिक है। बाजार में इस तेजी की प्रमुख वजह अमेरिकी और चीनी हाइपरस्केलर कंपनियों का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता निवेश बताया गया है। कोरिया एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक के रिसर्च सेंटर की ओर से वैश्विक बाजार अनुसंधान कंपनियों के विश्लेषण के आधार पर तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे पहले लगाए गए अनुमान में 2030 तक बाजार के एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना जताई गई थी। नए अनुमान से पता चलता है कि एआई से जुड़ी मांग ने उद्योग के विकास की रफ्तार को काफी तेज किया है। रिपोर्ट के अनुसार बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर संचालित करने वाली अमेरिका और चीन की प्रमुख कंपनियां एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश बढ़ा रही हैं। एआई सिस्टम में डेटा की मात्रा बढ़ने के साथ उच्च क्षमता वाली मेमोरी चिप्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा लाभ मेमोरी चिप निर्माताओं को मिल रहा है और वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का विस्तार हो रहा है। एआई उद्योग के कुछ हिस्सों में तकनीक पर नियंत्रण खोने से जुड़ी चिंताओं के कारण इसके विकास की गति धीमी करने की मांग भी उठ रही है। इसके बावजूद सेमीकंडक्टर बाजार की रफ्तार फिलहाल बनी हुई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स द्वारा निर्मित मेमोरी चिप्स वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर सकती हैं। मेमोरी चिप्स की कीमतों में भी इस मांग का असर दिखाई दे रहा है। पिछले महीने के अंत तक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (डीआरएएम) और एनएएनडी फ्लैश मेमोरी चिप्स की कीमतें एक साल पहले की तुलना में क्रमश: 4.4 गुना और नौ गुना बढ़ चुकी थीं। हालांकि, नवीनतम अनुमानों में अगले साल से मेमोरी चिप्स की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद जताई गई है। इसके बावजूद मजबूत मांग के कारण वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार की वृद्धि जारी रहने की संभावना है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक यह बाजार करीब दो ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। एआई सेवाओं के विस्तार और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार हो रहे निवेश को बाजार की इस वृद्धि का प्रमुख आधार माना जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स जैसी मेमोरी चिप निर्माता कंपनियों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते कर रही हैं।

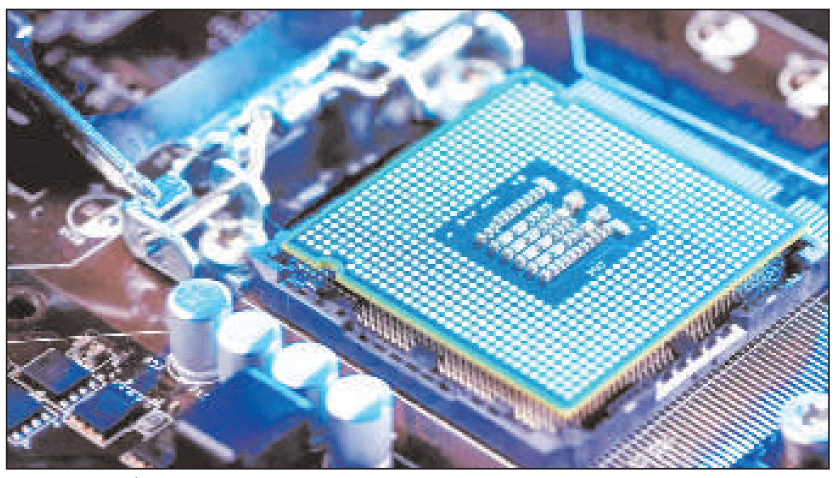

स्मॉलकैप के 64 फीसदी शेयरों में म्युचुअल फंडों ने बढ़ाई हिस्सेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी। अगस्त 2026 में म्युचुअल फंडों ने निफ्टी स्मॉलकैप 100 में शामिल अधिकांश शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की सितंबर 2026 की फंड फोलियो रिपोर्ट के अनुसार, म्युचुअल फंड निफ्टी स्मॉलकैप 100 के 64 प्रतिशत शेयरों में खरीदार रहे। यह आंकड़ा स्मॉलकैप कंपनियों में फंडों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में सबसे ज्यादा खरीदारी टेनेको क्लीन एयर इंडिया और केफिन टेक्नोलॉजीज में हुई। टेनेको क्लीन एयर इंडिया में म्युचुअल फंडों की होल्डिंग 129.5 प्रतिशत बढ़कर 5.82 करोड़ शेयर हो गई। अगस्त के अंत तक इन शेयरों का मूल्य करीब 80.8 अरब रुपये रहा। यह स्मॉलकैप शेयरों में फंडों की ओर से की गई प्रमुख खरीदारी में शामिल रहा। इसके बाद केफिन टेक्नोलॉजीज में म्युचुअल फंडों की हिस्सेदारी में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कंपनी में फंडों की होल्डिंग बढ़कर 4.51 करोड़ शेयर हो गई। इसके अलावा अर्बन कंपनी में फंडों की हिस्सेदारी 29.2 प्रतिशत, हिंदुस्तान कॉपर में

28.7 प्रतिशत और एस्टर डीएम क्वालिटी में 27.7 प्रतिशत बढ़ी। हालांकि, सभी स्मॉलकैप शेयरों में म्युचुअल फंडों ने खरीदारी नहीं की। कुछ कंपनियों में फंडों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। हिमाद्री स्पेशियलिटी केमिकल में म्युचुअल फंडों की होल्डिंग 56.8 प्रतिशत घटकर करीब 26 लाख शेयर रह गई। इसी तरह जीएमडीसी में फंडों की हिस्सेदारी 46.7 प्रतिशत कम हुई। इसके अलावा आईआईएफएल फाइनेंस, एमआरपीएल और सारदा एनर्जी में भी म्युचुअल फंडों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई। इससे पता चलता है कि अगस्त में फंडों की गतिविधियां केवल खरीदारी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अलग-अलग कंपनियों में उनके निवेश को लेकर बदलाव भी देखने को मिला।

चीन पर निर्भरता घटाने के लिए 5,000 7,000 करोड़ की योजना की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। उद्योग निकाय एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसीएफआई) ने कृषि रसायन तकनीकी और मध्यवर्ती उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार से 5,000 से 7,000 करोड़ रुपये की सहायता योजना लाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि इससे चीन के कम लागत वाले लाभ का मुकाबला करने और घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। एसीएफआई ने परामर्श फर्म केपीएमजी के सहयोग से तैयार रिपोर्ट में सात से आठ वर्ष की अवधि वाले कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत पहले दो से तीन वर्षों में संयंत्र स्थापित करने और इसके बाद उत्पादन को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा सकती है। संगठन का मानना है कि इस तरह चरणबद्ध

तरीके से सहायता देने से उद्योग को उत्पादन क्षमता विकसित करने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। रिपोर्ट में नई और मौजूदा विस्तार परियोजनाओं, दोनों को योजना में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत बड़ी और छोटी इकाइयों के लिए निवेश की क्रमिक सीमा तय करने का प्रस्ताव है। एसीएफआई के अनुसार इस व्यवस्था से विभिन्न स्तर के उद्योगों को अपनी क्षमता बढ़ाने और कृषि रसायन क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिल सकती है। एसीएफआई ने वृद्धिशील बिक्री पर पांच से आठ प्रतिशत प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा औद्योगिक बिजली और साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्रों पर 30 से 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। संगठन का कहना है कि उत्पादन लागत से जुड़ी इन चुनौतियों को दूर करना घरेलू कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है। रिपोर्ट में विशेष अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए पूंजीगत अनुदान देने की भी मांग की गई है। एसीएफआई के अनुसार कृषि रसायन तकनीकी और मध्यवर्ती उत्पादों के क्षेत्र में घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देना जरूरी है।

अमेरिकी टैरिफ से भारतीय कपड़ा उद्योग चिंतित, निर्यात पर बढ़ा संकट

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी बाजार में भारतीय कपड़ा और परिधान निर्यात पर नए शुल्कों का खतरा मंडराने से उद्योग की चिंता बढ़ गई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआईटीआई) ने कहा है कि अमेरिका भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में वहां अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की स्थिति में भारतीय निर्यात पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। इस फैसले ने भारतीय कपड़ा उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उद्योग को आशंका है कि यदि इस कानून के तहत भारत पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाया गया तो निर्यात कारोबार पर गंभीर दबाव पड़ सकता है। सीआईटीआई के वरिष्ठ अधिकारी चंद्रन ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की स्थिति में कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए इसका सामना करना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि खासतौर पर

छोटे और मझोले उद्योगों के सामने चुनौती अधिक गंभीर हो सकती है। ये उद्योग पहले से ही कई तरह की कारोबारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। चंद्रन के अनुसार नए शुल्क भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद बेचना और कठिन बना सकते हैं। इससे भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात पर नकारात्मक दबाव पड़ने की आशंका है। अमेरिका भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बाजार है, इसलिए वहां कारोबार में आने वाली किसी भी बड़ी बाधा का असर निर्यातकों की गतिविधियों पर पड़ सकता है। उद्योग ने भारत सरकार से अमेरिका के साथ बातचीत तेज करने का आग्रह किया है, ताकि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में कारोबार की राह में अतिरिक्त बाधाएं न आएं। सीआईटीआई ने भारत और अमेरिका के बीच निष्पक्ष, संतुलित और बराबरी वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। उद्योग का कहना है कि अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों से भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं, लेकिन उनका लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। कंपनियों को नए बाजारों में अपनी स्थिति बनाने के लिए समय और लगातार प्रयास की जरूरत होगी। इसलिए निकट भविष्य में अमेरिकी बाजार से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई इन नए बाजारों से करना आसान नहीं होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के अगले साल लागू होने की उम्मीद है। वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। उद्योग को इन समझौतों से नए अवसर मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल अमेरिकी शुल्क को लेकर चिंता बनी हुई है और सरकार से भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की अपील की गई है।

सीएसके पर फिर फिक्सिंग का साया, एजीएम में चर्चा करेंगे अधिकारी, रचित भाटिया ने युवा क्रिकेटर को फंसाया

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स पर एक बार फिर फिक्सिंग का साया मंडरा रहा है। टीम के एक खिलाड़ी पर आईपीएल 2025 के दौरान प्लेइंग 11 और अन्य जानकारियां देने का आरोप लगा है। ये जानकारी मैच से पहले ही सटोरियों तक पहुंचा दी गई थी। रचित भाटिया नाम के एक पूर्व क्रि केटर के स्टिंग ऑपरेशन में यह खुलासा हुआ है। तहलका स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि आईपीएल 2025 में चेन्नई के पांच मैच की जानकारी पहले ही सटोरियों तक पहुंचाई गई। हर मैच के लिए रचित को 60 लाख रुपये मिले और पूरे सीजन में उन्हें कुल 3 करोड़ रुपये सटोरियों से मिले।

रचित भाटिया ने इस स्टिंग ऑपरेशन में एक युवा खिलाड़ी के बारे में भी बताया है। भाटिया के अनुसार यह खिलाड़ी दिल्ली का रहने वाला है। आईपीएल 2025 में चेन्नई का हिस्सा था और चेन्नई की जानकारी लीक की। वहीं, दिल्ली प्रीमियर लीग में भी यह खिलाड़ी मैच फिक्स करने, धीमी बल्लेबाजी करने और अन्य जानकारियां देने के लिए तैयार है। भाटिया ने जिस खिलाड़ी की तरफ इशारा किया, उसकी प्रोफाइल वंश बेदी से मिलती है। हालांकि, डीडीसीए साफ कर चुका है कि वंश ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं थे।

कैसे हुआ खुलासा?

तहलका स्टिंग ऑपरेशन में एक रिपोर्टर ने सट्टेबाज बनकर रचित भाटिया से बात की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आईपीएल 2025 के मैच की जानकारी उन्होंने लीक कराई थी। 2026 में उनका सूत्र फिट नहीं था। ऐसे में आईपीएल का हिस्सा नहीं बना और वह ऐसा नहीं कर सके। हालांकि, भाटिया ने दावा किया कि वह दिल्ली प्रीमियर लीग के दौरान स्पॉट फिक्सिंग तक करा सकते हैं। वंश बेदी आईपीएल 2025 के दौरान चेन्नई की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें चोट लग गई थी। ऐसे में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया।

अगले सीजन में किसी ने उन पर दांव नहीं लगाया और आईपीएल से बाहर रहे। हालांकि, भाटिया के स्टिंग ने वंश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन वह खुद और डीडीसीए भी इस तरह के सभी आरोपों से इंकार कर चुका है। वंश ने लीगल एक्शन की चेतावनी देते हुए लिखा कि वह उनका नाम खराब करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे।

एजीएम में होगी चर्चा

सीएसके की एजीएम 25 सितंबर को होनी है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले मैच फिक्सिंग मामले पर चर्चा करने के लिए अधिकारी तैयार हैं। चेन्नई से जुड़े गुरुनाथ मयप्पन फिक्सिंग की घटनाओं में लिप्त पाए गए थे। इसके बाद साल 2016 और 2017 में चेन्नई की टीम दो साल के लिए आईपीएल से बैन हुई थी।

आईपीएल का सबसे बड़ा अधिग्रहण करने जा रहे लक्ष्मी मित्तल और अदार पूनावाला

राजस्थान रॉयल्स, खरीदने 15,838 करोड़ की मेगा डील तकनीबन पक्की हुई

मुम्बई (यशभारत)। स्टील किंग लक्ष्मी एन मित्तल और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ अदार पूनावाला ने मिलकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को खरीदने की मेगा डील लगभग पूरी कर ली है। इस बड़े अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भी आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह ऐतिहासिक सौदा लगभग 1.65 अरब डॉलर (करीब 15,838.63 करोड़) में तय हुआ है, जो आईपीएल फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे बड़े सौदों में से एक है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इस अधिग्रहण को 17 सितंबर को ही अपनी मंजूरी दे दी थी। ऐसे में अब इस डील के पूरा होने की कानूनी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मित्तल और पूनावाला के इस अधिग्रहण पैकेज में केवल राजस्थान रॉयल्स ही नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी के मालिकाना अधिकार वाली दो विदेशी क्रिकेट टीमें दक्षिण् अफ्रीका की टी-20 लीग 20 में भाग लेने वाली पार्ल रॉयल्स और वेस्टइंडीज कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में खेलने वाली बारबाडोस रॉयल्स भी अब मित्तल और पूनावाला के मालिकाना अधिकार में आ जाएंगी। यह विस्तार दर्शाता है कि यह अधिग्रहण सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक क्रिकेट लीगों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महत्वाकांक्षी सौदा ब्रिटेन में पंजीकृत निवेश कंपनी वेस्टव्यू क्रिकेट लिमिटेड के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, जिसका स्वामित्व मित्तल परिवार के पास है। इस सौदे में पूनावाला स्पोर्ट्स एंड फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड भी एक प्रमुख हिस्सेदार है।

इस डील के तहत, मित्तल परिवार वेस्टव्यू क्रिकेट के माध्यम से फ्रेंचाइजी समूह की लगभग 75 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करेगा, जबकि अदार पूनावाला की हिस्सेदारी करीब 18फीसदी होगी। मौजूदा निवेशकों में शामिल मनोज बदाले के पास अपनी लगभग फीसदी हिस्सेदारी बरकरार रहने की उम्मीद है। इस सौदे की घोषणा इस साल की शुरुआत में ही लगभग 1.65 अरब डॉलर के एंटरप्राइज वैल्यू पर की गई थी, जो इसकी विशालता और क्रिकेट जगत में इसके महत्व को रेखांकित करता है। यह उल्लेखनीय है कि इस समझौते से पहले, अमेरिकी निवेशकों के नेतृत्व वाले एक समूह ने भी राजस्थान रॉयल्स को खरीदने का असफल प्रयास किया था, तब फ्रेंचाइजी समूह का मूल्यांकन लगभग 1.63 अरब डॉलर आंका गया था। मित्तल और पूनावाला जैसे दिग्गज उद्योगपतियों का राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ना फ्रेंचाइजी के लिए एक नया अध्याय खोलेगा और टीम को वित्तीय तथा रणनीतिक रूप से और भी मजबूत करेगा।

जहीर को धोनी की सलाह पर सीएसके ने बनाया कोच ?

चेन्नई (यशभारत)। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ज़हीर ख़ान को अपना नया मुख्य कोच बनाया है। माना जा रहा है कि सीएसके के इस फैसले के पीछे टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अहम भूमिका होगी। धोनी की सलाह पर ही सीएसके ने जहीर को कोच की जिम्मेदारी सौंपी होगी। यह नियुक्ति फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि ज़हीर ने उस लंबे कोचिंग कार्यकाल की जिम्मेदारी ली है जो पिछले कई वर्षों से टीम की सफलता का सबसे मजबूत आधार रहा है। इसी कारण जब टीम के लिए नए कोच की तलाश शुरू हुई, तो कई विदेशी और देसी दिग्गजों के बड़े-बड़े नाम दौड़ में शामिल थे पर इसके बाद भी सीएसके ने जहीर के अवसर दिया। सीएसके के क्रिकेट प्रबंधन पर धोनी का प्रभाव है, ऐसे में सोच थी कि टीम की कमान किसी ऐसे भारतीय दिग्गज को सौंपी जाए जो घरेलू स्तर पर युवाओं की नब्ज़ पहचानता हो। वहीं ज़हीर न केवल एक चतुर रणनीतिकार हैं, बल्कि खेल की उनकी समझ असाधारण है। धोनी भली-भांति जानते हैं कि टीम इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रही है, जहाँ नए और युवा खिलाड़ियों को तैयार करना है। ऐसे में ज़हीर से बेहतर क्रिकेटिंग दिमाग वाला कोच कोई दूसरा कोई नहीं हो सकता था। पूर्व में अन्य बड़ी फ़्रेंचाइज़ी के साथ काम करने के ज़हीर के रणनीतिक अनुभव का लाभ भी सीएसके को मिलेगा। धोनी और ज़हीर का रिश्ता महज़ एक कप्तान और गेंदबाज़ का नहीं रहा है। यह अटूट विश्वास और सम्मान की कहानी है। भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम दौर, विशेषकर 2011 के ऐतिहासिक विश्व कप अभियान में इन दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी, जहाँ ज़हीर भारत के सबसे सफल गेंदबाज़ बनकर उभरे थे।

इरफान बोले, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में यशस्वी को सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारें

मुम्बई (यशभारत)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की घरेलू एकदिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम की संभावित अंतिम ग्यारह को लेकर अपने सुझाव दिये हैं। पठान का कहना है कि 27 सितंबर से शुरू होने वाली इस सीरीज में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरा जाना चाहिये। जिससे कि वह 2027 एकदिवसीय विश्व कप से पहले लय हासिल कर सके। पठान के अनुसार, यशस्वी को रोहित के साथ पारी की शुरुआम करते हुए देखा जा सकता है, जबकि विराट कोहली नंबर-3 पर उतरेंगे। इरफान पठान ने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ यह सीरीज यशस्वी जैसे खिलाड़ियों के लिए अहम है। उन्होंने कहा, जायसवाल आपके बैकअप ओपनर हैं, फिलहाल वह आपके तीसरे सलामी बल्लेबाज हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण दौरों से पहले यह पक्का करना होगा कि आपके बैकअप ओपनर को पर्याप्त अवसर मिलें। जायसवाल ने अब तक खेले छह एकदिवसीय मैचों में दो शतक लगाकर अपनी उपयोगिता साबित की है और शुभमन गिल व रोहित शर्मा के बाद वह एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस एकदिवसीय सीरीज में भारतीय टीम में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुख्य टीम एशियाई खेलो के लिए जापान गयी है। इसी को देखते हुए पठान ने कहा कि ये उन खिलाड़ियों के लिए अपने को साबित करने का अच्छा अवसर है जिन्हें श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों के टीम में नहीं होने के कारण अवसर मिला है। साथ ही कहा कि यह एक तरह की दूसरी टीम है जिसमें कई खिलाड़ियों को आजमाया जा रहा है। इससे ध्रुव जुरेल और गुरनूर बरार जैसे खिलाड़ियों के पास अच्छा अवसर है। पठान ने इस बात पर भी जोर दिया कि घरेलू सीरीज में बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना टीम सही कदम है। उन्होंने कहा, आप वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं। आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी, क्योंकि अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले आपको 11 मैच खेलने को मिलेंगे। इन मैचों में आप बेंच स्ट्रेंथ को भी देखना चाहेंगे।

आयुष्मान खुराना ने चुपके से की मदद, अब शोर मचा रही मेघना की सफलता, बताया- एक खबर ने बदली जिंदगी

भारतीय निशानेबाज मेघना सज्जनार ने बताया है कि बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने मुश्किल समय में उनकी मदद की थी। खास बात यह है कि उस समय वह मेघना को जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में मेघना के बारे में पढ़ा और मदद करने का फैसला किया। उनकी मदद के दम पर मेघना इस मुकाम तक पहुंची हैं कि करोड़ों देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर रही है। आयुष्मान की मदद से मेघना को विश्व स्तरीय राइफल मिली, जिससे उन्हें बिना किसी परेशानी के प्रतियोगिताओं की तैयारी और अभ्यास जारी रखने में मदद मिली। अब इसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। मेघना ने हाल ही में यहां कर्णी सिंह निशनेबाजी परिसर में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता। इसके अलावा, उन्होंने काहिरा में आयोजित 2022 और 2025 विश्व चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक अपने नाम किए हैं।

रंग संसार

फोबे डायनेवर ने कैमरून फुलर संग रचाई शादी

मुंबई (यशभारत)। नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज़ ब्रिजर्टन से दुनियाभर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री फोबे डायनेवर ने प्रोड्यूसर कैमरून फुलर से शादी कर ली है। फोबे ने अपनी इस खुशख़बरी की पुष्टि स्वयं इंस्टाग्राम पर नवविवाहित जोड़े की तस्वीरें साझा करके की, जिसमें वे सेरेमनी आर्च के पास किस करते और एक साथ चलते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी की। कैमरून फुलर ने भी प्यार भरे इमोजी के साथ इस घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। उनकी ब्रिजर्टन की सह-कलाकार सिमोन एशले और बीच रीड के सह-कलाकार पैट्रिक श्वार्ज़नेगर सहित कई दोस्तों और प्रशंसकों ने जोड़े को बधाई दी।

जेलर 2 में विद्या बालन का फर्स्ट लुक जारी, मचाई खलबली

मुंबई (यशभारत)। बहुप्रतीक्षित फिल्म जेलर 2 के फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में अभिनेत्री विद्या बालन का पहला लुक साझा किया है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार की इस फिल्म में विद्या बालन कांता नामक एक शक्तिशाली किरदार में नज़र आएंगी, और उनकी एंट्री से प्रशंसकों की उत्सुकता दोगुनी हो गई है।

सुपरस्टार रजनीकांत और विद्या बालन अभिनीत इस फिल्म के मेकर्स द्वारा जारी किए गए वीडियो में, विद्या बालन नीली साड़ी पहने सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके हाथ में जलती हुई सिगरेट है और वे बेहद बेबाकी से धुएं का छल्ला उड़ाती नज़र आती हैं। अनिरुद्ध रविचंदर के दमदार बैकग्राउंड स्कोर ने इस दृश्य को और भी प्रभावशाली बना दिया है। यह सीन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बड़े पर्दे पर कांता बनकर विद्या बालन, रजनीकांत के किरदार को कड़ी टक्कर देने वाली हैं। विद्या बालन के किरदार से पर्दा उठाने से ठीक पहले, मेकर्स ने सूरज वेंजारामूडु के दमदार रोल की झलक भी पेश की थी। टीज़र में सूरज एक नए और स्टाइलिश लुक में गाड़ी से उतरते हुए सिगार के छल्ले उड़ाते दिखे थे। इसके अलावा, जेलर 2 में एस.जे. सूर्या की एंट्री ने भी प्रशंसकों का उत्साह बढ़ाया है। फिल्म में वे बोधी के दिलचस्प किरदार में नज़र आएंगे। यह पहला मौका है जब एस.जे. सूर्या बड़े पर्दे पर रजनीकांत के साथ स्क्रीन साझा करते दिखेंगे, जिससे फिल्म के प्रति दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।

रजनीकांत की जेलर 2 की कमान नेल्सन दिलीपकुमार के हाथों में है, जिन्होंने इस सीक्वल को लिखा और निर्देशित किया है। यह साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर का सीक्वल है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।

हनुमान अंश की टीम से मिले सीएम फडणवीस

हाल ही में फ्लि्म हनुमान अंश की टीम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके आवास वर्षा में मुलाक़ात की और गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस भेंट का सबसे अहम पहलू यह रहा कि मुख्यमंत्री ने फ्लि्म के निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी और उनकी पूरी टीम के उत्कृष्ट कार्य की व्यक्तिगत रूप से सराहना की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुलाक़ात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करते हुए हनुमान अंश की टीम को गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए वर्षा में स्वागत करने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने डॉ. विशाल चतुर्वेदी और उनकी टीम को उनके शानदार काम के लिए बधाई दी और उनके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए सफलता की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपनी मातृभाषा मराठी में भी टीम को शुभकामनाएं दीं और उनके रचनात्मक प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर

जब काजी तौकीर बिग बॉस 20 के घर में आए, तो शायद कई युवा दर्शकों का रिएक्शन यही था-ये कौन हैं? लेकिन जिन लोगों ने 2000 के दशक के बीच में रियलिटी टेलीविजन देखा था, उनके लिए उनका चेहरा और उनकी जबरदस्त पर्सनैलिटी एक अलग ही याद लेकर आई। फेम गुरुकुल जीतने के लगभग 21 साल बाद, काजी रियलिटी-टीवी की लाइमलाइट में वापस आ गए हैं, और इस बार, उनका मनोरंजक अंदाज ही चर्चा का विषय बना हुआ है। काजी सिर्फ 20 साल के थे जब 20 अक्टूबर, 2005 को रूपरेखा बनर्जी के साथ फेम गुरुकुल की विजेता फेम जोड़ी का हिस्सा बने थे।

गाना आजा गुफाओं में आ महिला शक्ति का प्रतीकः रवीना टंडन

मुंबई (यशभारत)। अपनी फिल्म अक्स के मशहूर गाने आजा गुफाओं में आ के रीक्रिएशन पर अभिनेत्री रवीना टंडन ने ऐतराज जताया है। रवीना टंडन का कहना है कि यह गीत डरावना नहीं, बल्कि बेहद खूबसूरत और महिलाओं की शक्ति को दर्शाने वाला गीत है, जिसे आजकल गलत तरीके से हॉरर फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जा रहा है। रवीना टंडन हाल ही में डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 के सेमीफाइनल एपिसोड में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस दौरान प्रतियोगी गीतांजलि और कोरियोग्राफर अनुराधा ने आजा गुफाओं में आ और ये रात गीतों पर एक शानदार प्रस्तुति दी, जिसने जजों और रवीना टंडन दोनों को प्रभावित किया। हालांकि, रवीना ने प्रस्तुति को फ्लॉलेस बताते हुए भी एक शिकायत जाहिर की।

'स्पिरिट' को लेकर शुरू हुआ विवाद नहीं ले रहा थमने का नाम

मुंबई (ईएमएस)। फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मशहूर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म से अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद कई तरह की अटकलें सामने आईं। कभी काम के घंटों को लेकर चर्चाएं हुईं तो बाद में फिल्म के मुनाफे में हिस्सेदारी और कहानी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक होने के आरोपों ने विवाद को और बढ़ा दिया। हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी की ओर से दीपिका पादुकोण पर फिल्म के मुनाफे में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी मांगने और फिल्म से संबंधित कुछ जानकारियां लीक होने के आरोप लगाए जाने की चर्चा सामने आई थी। इसके बाद अब दीपिका की सोशल मीडिया गतिविधि ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट को लाइक किया, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा और उनके भाई के रुख पर सवाल उठाए गए थे। पोस्ट में दीपिका के फैसले का समर्थन करते हुए कहा गया था कि उन्होंने ऐसी शर्तें रखीं, जो फिल्म उद्योग में पुरुष कलाकारों के लिए असामान्य नहीं मानी जातीं। पोस्ट में यह भी तर्क दिया गया कि किसी महिला कलाकार द्वारा अपनी पेशेवर शर्तें रखने या किसी प्रस्ताव को ठुकराने पर उसे अलग नजरिए से देखना लैंगिक असमानता का संकेत हो सकता है। बताया गया कि एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर विस्तृत टिप्पणी करते हुए प्रणय रेड्डी के उस कथित बयान पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें दीपिका द्वारा फिल्म के मुनाफे में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी मांगने की बात कही गई थी। इसी पोस्ट को दीपिका द्वारा लाइक किए जाने के बाद इसे उनके आरोपों पर अप्रत्यक्ष जवाब के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, दीपिका पादुकोण ने इस मामले पर कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी ओर से पोस्ट को लाइक करने की घटना ने ही नई बहस को जन्म दे दिया है। दीपिका के फिल्म से बाहर होने के बाद 'स्पिरिट' में अभिनेत्री तृप्ति डिमरी को प्रभास के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में शामिल किया गया। फिल्म में अभिनेता विवेक ओबेरॉय भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म को 5 मार्च 2027 को रिलीज करने की योजना बताई जा रही है। वहीं, दीपिका पादुकोण के आगामी प्रोजेक्ट्स में शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' और निर्देशक एटली की फिल्म 'राका' शामिल बताई जा रही हैं, जिसमें वह अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ नजर आ सकती हैं।

पुलिस कांस्टेबल बैंड भर्ती पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

इंदौर, । पुलिस कांस्टेबल (बैंड) पद पर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। याचिकाकर्ताओं और शासन का पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब निर्णय जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा सकेगी या नहीं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तीसरे चरण यानी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। याचिका में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के निर्धारित मापदंड को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना था। इसके विपरीत विभाग ने केवल दो गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया। याचिकाकर्ताओं ने पात्र अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया है। शासन की ओर से याचिका निरस्त करने की मांग करते हुए तर्क दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है और उसी के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। शासन ने यह भी बताया कि साक्षात्कार की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। बुधवार को न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने पूर्व में प्रस्तुत तर्कों को दोहराया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

वन सेवा मुख्य परीक्षा 27 सितंबर को, 692 अभ्यर्थी होंगे शामिल

इंदौर के दो केंद्रों पर होगी परीक्षा, सीसीटीवी-बायोमेट्रिक से निगरानी

इंदौर । मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा-2026 27 सितंबर को इंदौर के दो परीक्षा केंद्रों पर होगी। ऑफलाइन परीक्षा दोपहर 12 से 3 बजे तक एक सत्र में आयोजित की जाएगी। इसमें 692 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा के लिए आयोग ने केंद्रों पर त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की है। सीसीटीवी सर्विलेंस, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र स्कैनिंग और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से तलाशी की जाएगी। निगरानी के लिए VOIP व्यवस्था भी रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले केंद्र पहुंचना होगा। प्रवेश द्वार पर अनुमत और प्रतिबंधित वस्तुओं की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की जांच संबंधित वीक्षकों द्वारा की जाएगी, जबकि ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को महिला या पुरुष कर्मचारी से जांच कराने का विकल्प रहेगा। अभ्यर्थी केवल बॉलपेन, पारदर्शी पानी की बोतल, ई-प्रवेश पत्र और आईडी कार्ड साथ ला सकेंगे। आवश्यक दवाइयां ले जाने की अनुमति भी होगी। आयोग ने समय से पहले केंद्र पहुंचने और सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

इंदौर-खडकी स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़े, नवंबर तक चलेगी ट्रेन

इंदौर, यशभारत। यात्रियों की सुविधा और आगामी त्योहारों के दौरान बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर-खडकी (पुणे) स्पेशल ट्रेन के फेरों का विस्तार किया है। अब यह ट्रेन नवंबर के अंतिम सप्ताह तक संचालित होगी। रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि ट्रेन संख्या 09324 इंदौर-खडकी स्पेशल 7, 14, 21 और 28 अक्टूबर तथा 4, 11, 18 और 25 नवंबर 2026 को इंदौर से रवाना होगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09323 खडकी-इंदौर स्पेशल 8, 15, 22 और 29 अक्टूबर तथा 5, 12, 19 और 26 नवंबर 2026 को खडकी से इंदौर के लिए संचालित होगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन के कोच संयोजन, ठहराव, मार्ग और संचालन के दिनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ट्रेन का परिचालन पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ही जारी रहेगा। फेरों में विस्तार से त्योहारों के दौरान इंदौर और पुणे के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

सरकारी पट्टे की जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त

सनावदिया में 0.550 हेक्टेयर जमीन पर काटे प्लॉट और निर्माण पर चला बुलडोजर

इंदौर, यशभारत। सरकारी पट्टे की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर विकसित की जा रही कॉलोनी पर जिला प्रशासन ने बुधवार को कार्रवाई की। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर तहसील भिचौली हप्सी के ग्राम सनावदिया में निर्माणाधीन पक्के निर्माण और सड़कों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।एसडीएम अजय भूषण शुक्ला ने बताया कि भूमि स्वामी जितेंद्र पिता करण सिंह द्वारा सर्वे नंबर 680/1/1/2/3 और 680/1/1/2/6 की करीब 0.550 हेक्टेयर शासकीय पट्टे की भूमि पर अवैध प्लॉट काटकर बेचने और निर्माण शुरू करने की सूचना मिली थी। इसके बाद एसडीएम शुक्ला, तहसीलदार अनिल पटेल, अजय अहिरवार, राजस्व अमले और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन पक्के निर्माण और कॉलोनी की सड़कों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार मामले में बने सिंह, चम्पालाल और जितेंद्र के खिलाफ अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामले में पहले से एफआईआर दर्ज है।प्रशासन ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

25 सितंबर को फिर सजेगा इंदौर, 103 साल पुरानी झांकी परंपरा में दिखेगा आधुनिक तकनीक का रंग

इंदौर, यशभारत। शहर की 103 वर्ष पुरानी अनंत चतुर्दशी झांकी परंपरा एक बार फिर 25 सितंबर को जीवंत होने जा रही है। मिलों की झांकियां तैयार हो चुकी हैं और इन दिनों विद्युत सज्जा, पुतलों, चलित मॉडलों और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जा रहा है। इस बार धार्मिक प्रसंगों के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को भी झांकियों में शामिल किया गया है।झांकियों के निर्माण में एआई, थ्रीडी और हाइड्रोलिक तकनीक के साथ चलित मॉडल, रोशनी और ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया गया है। पहली बार राजकुमार मिल की एक झांकी दो ट्रालों को जोड़कर करीब 60 फीट लंबी तैयार की गई है। इसमें भगवान विष्णु और असुर मधु-

कैटभ के युद्ध का प्रसंग दिखाया जाएगा। इसके अलावा जगन्नाथ रथयात्रा और अशोक वाटिका भी झांकियों में नजर आएगी।

कल्याण मिल में दिखेगी नारी शक्ति

कल्याण मिल की नारी शक्ति थीम पर तैयार झांकी में आधुनिक तकनीक और चलित मॉडलों के जरिए अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को अंतरिक्ष यान से 18 फीट ऊंचाई तक जाते हुए दिखाया जाएगा। वहीं भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। स्वदेशी मिल की तीन झांकियों में नशामुक्त हो भारत हमारा जैसे सामाजिक संदेश के साथ रुद्र अवतार और शुंभ-निशुंभ वध के प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे।

हुकुमचंद मिल में सिंदूरासुर वध

हुकुमचंद मिल की तीन झांकियों में सिंदूरासुर राक्षस वध की कथा प्रमुख आकर्षण होगी। समिति अध्यक्ष नरेंद्र श्रीवंश के अनुसार झांकी में राक्षस की उत्पत्ति, भगवान गणेश से उसका युद्ध और सिंदूर अर्पित किए जाने की कथा को दर्शाया गया है। दूसरी झांकी बाली-सुग्रीव युद्ध पर आधारित है, जबकि तीसरी झांकी में वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा प्रस्तुत की जाएगी।होप टेक्सटाइल्स मिल इस वर्ष बिना किसी सरकारी अनुदान के दो झांकियां तैयार कर रही है। इनमें पहली झांकी गणेश आराधना पर आधारित है, जिसमें देवताओं द्वारा निर्विघ्न कार्य की कामना से भगवान गणेश की पूजा करते हुए दिखाया गया है। दूसरी झांकी में भगवान शिव की बारात होगी। इसमें नंदी, भूत-प्रेत और देवताओं के साथ दूल्हे के रूप में भगवान शिव का स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहेगा।

हर जिले में स्वास्थ्य सहायता समिति बनाएगा निव्राह फाउंडेशन

'आरोग्य भारत अभियान' के तहत बीमा जागरूकता और मरीजों की मदद पर जोर

इंदौर, यशभारत। स्वास्थ्य बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद मरीजों को उपचार में आर्थिक सहायता देने के लिए निव्राह फाउंडेशन देशव्यापी 'आरोग्य भारत अभियान' चलाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सहायता समिति और स्थानीय सहायता कोष बनाने का प्रस्ताव है। संगठन निःशुल्क सदस्यता अभियान भी शुरू करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विनायक अशोक लूनिया जैन की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में अभियान की रूपरेखा पर चर्चा हुई। अभियान के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा और मेडिक्लेम की उपयोगिता की जानकारी दी जाएगी। गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा जरूरत के मामलों में ाउडफंडिंग के जरिए सहायता जुटाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। विभिन्न शहरों में सामाजिक-सांस्कृतिक कार्य मों से जुटाई गई सहयोग राशि संबंधित क्षेत्र के स्वास्थ्य सहायता कोष में रखी जाएगी। इसका उपयोग जरूरतमंद मरीजों के उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए किया जाएगा।जिला समितियां स्थानीय उद्योगपतियों, व्यवसायियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सक्षम नागरिकों से सहयोग जुटाएंगी। पत्रकारों, युवाओं, महिलाओं, व्यवसायियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अभियान से जोड़ने के लिए निःशुल्क सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा।डॉ. लूनिया ने कहा कि अभियान

बेटमा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, 500 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा

50 से ज्यादा गांवों से पहुंचे युवा-किसान; नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद, फसल बीमा और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरा

इंदौर, यशभारत। बेटमा में कांग्रेस ने युवा एवं किसान संवाद के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। बियानी गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में बेटमा और घाटाबिल्लोद क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों से युवा, किसान और ग्रामीण पहुंचे। आयोजकों ने दावा किया कि इस दौरान 500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
कार्यक्रम मोथला दरबार मेहरबान सिंह कछावा के नेतृत्व में हुआ। इसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव सत्यनारायण पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और राधेश्याम मुवेल सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।नए सदस्यों का कांग्रेस नेताओं ने तिरंगा और कांग्रेस के चुनाव चिह्न वाले गमछे पहनाकर स्वागत किया। आयोजकों के अनुसार, शामिल होने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की थी, जबकि 100 से अधिक बुजुर्ग भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
उमंग सिंघार ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना

साधा। उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए टोकन लेकर लंबी कतारों में लग रहा है, जबकि शराब के लिए टोकन की जरूरत नहीं है। फसल बीमा को लेकर उन्होंने दावा किया कि किसानों से बीमा राशि लेने के बावजूद नुकसान की स्थिति में कई किसानों को बहुत कम मुआवजा मिल रहा है। सिंघार ने पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र में किसानों और युवाओं से जुड़े सवाल प्रमुखता से उठाएगी। विधानसभा की लाइव कार्यवाही को लेकर भी उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए।

:सोयाबीन, जमीन अधिग्रहण और कॉलेज का मुद्दा

सत्यनारायण पटेल ने सोयाबीन की खराब फसल का तत्काल सर्वे कराने और किसानों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने मास्टर प्लान और विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों की जमीनों के अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया। साथ ही बेटमा और गौतमपुरा में कॉलेज खोलने की घोषणाओं के बावजूद काम शुरू नहीं होने का दावा किया।पटेल ने राजनीतिक संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंखों में आंखें डालकर बात करने का साहस राहुल गांधी में है। उन्होंने मध्यप्रदेश में कांग्रेस द्वारा जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की बात कही। संवाद के दौरान ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी समस्याएं भी रखीं। सिंधीपुरा के ललित मकवाना ने बताया कि 1960 में 26 आदिवासी परिवारों को 350 बीघा जमीन के पट्टे मिले थे, जिसे अब अधिग्रहित किया जा रहा है। उन्होंने मामले में सुनवाई नहीं होने की बात कही।पुजारी संघ अध्यक्ष बैरागी ने मंदिर की जमीनों के अधिग्रहण पर रोक लगाने और 1974 के खाता-खसरा रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने की मांग रखी। रिंग रोड के लिए करीब 10 परिवारों की लगभग 12 बीघा कृषि भूमि अधिग्रहित किए जाने के बावजूद उचित मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत भी सामने आई।

70 साल पुराने पेड़ों को हरित धरोहर घोषित करने की मांग, कुएं-बावड़ियों के संरक्षण पर जोर

इंदौर, यशभारत। शहर की पहचान केवल सड़कों, इमारतों और बाजारों से नहीं, बल्कि वर्षों पुराने पेड़ों, कुएं-बावड़ियों और तालाबों से भी जुड़ी है। बढ़ते कंक्रीटीकरण के बीच इस प्राकृतिक विरासत के संरक्षण की मांग तेज हो गई है। पर्यावरण प्रेमी मंच ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पुराने पेड़ों और जलस्रोतों को बचाने के लिए कई कदम उठाने की मांग की है।मंच ने 70 से 75 वर्ष या इससे अधिक पुराने पेड़ों को 'हरित धरोहर' घोषित करने का सुझाव दिया है। ऐसे पेड़ों की पहचान कर उनकी जियो-टैगिंग और अलग ग्रीन हेरिटेज रजिस्टर तैयार करने की मांग की गई है, ताकि उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहे और विकास कार्यों की योजना बनाते समय इन्हें बचाने के विकल्प पहले से तलाशे जा सकें।पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों के आसपास किए गए सीमेंटीकरण और पेवरीकरण को हटाने की मांग भी की। उनका कहना है कि जड़ों के

आसपास जमीन पक्की होने से बारिश का पानी जमीन में नहीं पहुंचता, जिससे पेड़ों के स्वास्थ्य के साथ भूजल रिचार्ज भी प्रभावित होता है। पुराने और अनुपयुक्त ट्री-गार्ड हटाकर पेड़ों को पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया गया है।

पेड़ काटने से पहले तलाशें विकल्प

ज्ञापन में हुकुमचंद मिल, एमओजी लाइंस, मेट्रो, नया आयुर्वेदिक कॉलेज, न्यू एमवाय अस्पताल, मास्टर प्लान की सड़कें, रानी सराय, नया रेलवे स्टेशन और शास्त्री पुल सहित विभिन्न परियोजनाओं में 'पहले पेड़ बचाएं' नीति लागू करने की मांग की गई। मंच ने कहा कि किसी पेड़ को काटने से पहले डिजाइन या सड़क के अलाइनमेंट में बदलाव सहित सभी विकल्प तलाशे जाएं और कटाई को अंतिम विकल्प रखा जाए।

110 साल पुराने डोल में नगर भ्रमण पर निकले लड्डू गोपाल

जलझुलनी एकादशी पर राठौर समाज का डोल चल समारोह, राजबाड़ा से होते हुए पंढरीनाथ पर हुआ समापन

इंदौर,यशभारत। जलझुलनी एकादशी पर श्री सकल पंच राठौर समाज की 110 साल पुरानी डोल परंपरा के तहत लड्डू गोपाल और राधारानी नगर भ्रमण पर निकले। समाजवादी इंदिरा नगर स्थित राठौर विद्या निकेतन से सजे-धजे डोल में भगवान को विराजमान कर पूजा-अर्चना और आरती की गई। इसके बाद डोल चल समारोह लाबरिया भैरु, बियाबानी, कपड़ा मार्केट, खजुरी बाजार और राजबाड़ा होते हुए पंढरीनाथ पहुंचा, जहां पारंपरिक रूप से समापन हुआ। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने डोल का स्वागत किया और लड्डू गोपाल व राधारानी की आरती की। समाजबंधुओं के साथ अन्य समाजों के लोगों ने भी चल समारोह में सहभागिता की। राजबाड़ा स्थित पूर्वी क्षेत्र धार्मिक संगठन के मंच पर पं. मीत कश्यप ने डोल का स्वागत किया। डोल रवाना होने से पहले विधि-विधान से पूजन और आरती हुई। समाज के पदाधिकारियों का मालवी पगड़ी, पुष्पमाला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह में पूर्व पार्षद सोनू राठौर, अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के संरक्षक विनोद राठौर दादा, राम मंदिर निर्माण समिति संयोजक हरीश राठौर लड्डू बाबा, पं. नरेंद्र राठौर, विजय देवड़ा, देवकरण राठौर, अशोक राठौर और महिला मंडल अध्यक्ष संगीता देवड़ा सहित समाज के वरिष्ठजन मौजूद रहे। श्री सकल पंच राठौर समाज अध्यक्ष ललित राठौर और श्री राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष गोविंद राठौर (राठौर क्रांति) ने बताया कि डोल में लड्डू गोपाल और राधारानी को विराजमान कर आरती के बाद यात्रा शुरू की गई।

इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल में 500 मरीज रोज, 40 को सोनोग्राफी की जरूरत

इंदौर, यशभारत। पीसी सेठी शासकीय अस्पताल में मरीजों का दबाव लगातार बढ़ा हुआ है। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 500 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें लगभग 10 गर्भवती महिलाएं जांच और चेकअप के लिए आती हैं,

जबकि प्रतिदिन 12 से 15 महिलाओं की प्रसूति हो रही है। मरीजों की संख्या के अनुपात में अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं पर भी लगातार दबाव बना हुआ है। गर्भवती महिलाओं सहित अन्य मरीजों की जांच के लिए प्रतिदिन करीब 35 से 40 सोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा सप्ताह में केवल चार दिन ही उपलब्ध है। वर्तमान व्यवस्था के तहत मंगलवार, शनिवार और रविवार को सोनोग्राफी नहीं होती। इससे जरूरतमंद मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ता है।सोनोग्राफी की जरूरत को देखते हुए अस्पताल की एक गायनेकोलॉजिस्ट को सोनोग्राफी की ट्रेनिंग दी गई है। आपात स्थिति में उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सामान्य दिनों में भी सोनोग्राफी की मांग काफी अधिक रहती है, ऐसे में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार व्यवस्था संचालित की जा रही है।अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी भी बनी हुई थी। हाल ही में चार बांडेड डॉक्टरों की पदस्थापना की गई है, जिससे चिकित्सा सेवाओं में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं सुरक्षा गार्ड और लिफ्टमैन की आवश्यकता भी बनी हुई है। इसके लिए सीएमएचओ को पत्र भेजकर व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की गई है। पीसी सेठी अस्पताल में संचालित पीडियाट्रिक आईसीयू को अब जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए कर्मचारियों के साथ मशीनरी भी भेजी जा रही है। फिलहाल अस्पताल में बड़े आईसीयू के विस्तार के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए आगे की व्यवस्था स्थान की उपलब्धता पर निर्भर रहेगी।

मिलें बंद हुईं, लेकिन इंदौर की झांकी परंपरा आज भी जिंदा

इंदौर, यशभारत। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बुधवार को मालवा मिल परिसर पहुंचकर झांकी निर्माण में जुटी समितियों को कुल एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने विभिन्न समितियों के प्रतिनिधियों को 25-25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की। इंदौर की अनंत चतुर्दशी झांकी परंपरा 100 वर्ष से अधिक पुरानी सांस्कृतिक विरासत मानी जाती है।
वर्मा ने कहा कि मिलें भले बंद हो गई हों, लेकिन मिल मजदूरों ने अपनी मेहनत, कला और आस्था के जरिए इंदौर की झांकी परंपरा को आज भी जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि ये झांकियां केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शहर के श्रमिक इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं।उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि उनके पास नगरीय प्रशासन विभाग होता तो प्रत्येक मिल की झांकी समिति को नगर निगम और इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कम से कम 10-10 लाख रुपये की सहायता दिलवाते। वर्मा ने महंगाई के कारण झांकियों के निर्माण की

बढ़ती लागत का हवाला देते हुए सहायता राशि बढ़ाने की मांग की।वर्मा ने सरकार पर गरीब और मेहनतकश वर्ग की अपेक्षित चिंता नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि झांकी समितियों को आर्थिक संरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने इंदौर के उद्योगपतियों, व्यवसायियों और सामाजिक संस्थाओं से भी मिल मजदूरों की इस सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण के लिए सहयोग की अपील की।उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अनंत चतुर्दशी की ऐतिहासिक झांकी परंपरा को संस्कृति विभाग से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इसे स्थायी और बजटीय सहयोग मिल सके।
वर्मा ने कहा कि वे हर वर्ष अपनी ओर से झांकी समितियों को सहयोग देते रहे हैं और आगे भी मिल मजदूरों की समस्याओं तथा उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए काम करते रहेंगे। सहायता प्राप्त करने वालों में मालवा मिल एवं कल्याण मिल से कैलाश कुशवाह, हरनाम सिंह धारीवाल, सुरेंद्र शर्मा, लक्ष्मीनारायण पाठक, देवी सिंह सेंगर और गुड्डू ठाकुर, स्वदेशी मिल से कन्हैयालाल मरमट और चंपालाल शर्मा तथा हुकुमचंद मिल से नरेंद्र श्रीवंश और किशनलाल बोकरे शामिल रहे। कार्यक्रम में इंटक नेता श्याम सुंदर यादव सहित बड़ी संख्या में मिल मजदूर, झांकी समितियों के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

स्वामी,प्रकाशक, मुद्रक आशीष कुमार शुक्ला, पी.जी.इंफ्रास्टचर एंड सर्विस प्रा.लि. राऊखेड़ी देवास रोड,इंदौर (मप्र) से मुद्रित एवं 22/1,पगनिसपागा पालसिकर कॉलोनी बालनिकेतन स्कूल के पास, इंदौर (म.प्र) 452007 से प्रकाशित | संपादक अम्बरीष तिवारी * प्रबंध संपादक अमरीश पचोरिया*, सलाहकार संपादक श्याम कटारे RNI No .MPHIN/26/A1896 फ़ोन – 9111201000 email – indoreyashbharat@gmail.com , (*पी.आर.बी.एक्ट के तहत समचार चयन के लिए जिम्मेदार) (न्यायालयीन क्षेत्राधिकार जबलपुर)